Postal Registration No. CHD/0107/2015-2017 RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 14 अंक 04 30 अप्रैल 2015 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से

भूमि अधिग्रहण महज एक चिंतन

फकीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

किसान तो गीता के उपदेश को मान्य रखकर ''कर्म किए जा रहा है, फल की इच्छा का उससे कोई सरोकार नहीं है - कम वर्षा तब भी दिक्कत, अधिक वर्षा तब भी दिक्कत। मौसम की मार - कर्ज, मर्ज, गर्ज की तबको, चोरी चकारी, पशु पक्षी कीट और दलाल सबकी मार झेलते हुए भी खेती से जुड़ा है, खेती घाटे का व्यवसाय है, क्योंकि इसके सिवाए उसको ना कुछ आता है ना भाता है। भूमि अधिग्रहण उसके जीवन में एक ग्रहण सा है जब भूमि ही नहीं रहेगी- खेती कहां करेगा। कोई दूसरी राय नहीं है कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि कृषि के साथ उद्योग की भी जरूरत है। सीमित भूमि के बीच ही एक मध्यम रास्ता अपनाना है ताकि निवेश भी हो सके और कृषि भी चलती रहे। कभी भारत अनाज उत्पादन अपनी जरूरत के अनुसार भी पैदा नहीं कर पाता था आज हमारे किसानों ने सख्त मेहनत कर इतना पैदा कर दिया है कि उसे उठाने वाला नहीं है। कृषि-उद्योग ही इसका समाधान कर सकते हैं। किसान की फसली जरूरतें - खाद, कीटनाशक, बिजली, पानी, सड़के, मकान और सुरक्षा व्यवस्था सभी परियोजनाओं के लिए भूमि की जरूरत है। आज राजनेता अपनी राजनैतिक रोटियां सेक रहा है। उसका किसान हितैषी एक दिखावा मात्र है। दो धारी तलवार की तरह का आचरण निभाते हैं। इस बार मौसम की मार के इलावा यूरीया में भी धांधली हुई है। सब्सिडी किसान के नाम की खा गए अधिकारी और दलाल सत्ताधारियों से मिलकर। किसान को यूरीया ब्लैक में खरीद कर बुआई करनी पड़ी। कीटनाशक बार-बार लेने पड़े क्योंकि बार-बार बरसात ने धो डाले।

भूमि अधिग्रहण के नाम जो लूटखसूट होती है, उसे इतिहास कभी माफ नहीं कर सकता। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का जिक्र कभी नहीं आता। क्या किसानों को रोटी खाने का हक नहीं है? जाते-जाते भूमि अधिग्रहण अध्यादेश बिल पारित करवाने पर सरकार अडिग है आज किसान हितैषी का दम भर रहे हैं। सर्व विदित है कि भूमि संसाधान सीमित हैं। राष्ट्र विकास हेतू विदेशी निवेश की नितांत जरूरत है। प्रधानमंत्री का नारा है - 'मेक इन इंडिया' क्योंकि अपने संसाधनों से औद्योगिक विकास के इलावा कृषि उत्पादन में भी इजाफा संभव नहीं है। किसान पूर्णतया सजग है और कार्यरत है। उसे उसकी मेहनत का फल मिलना भी नितांत जरूरी है जो केवल उत्पादकता बढाकर ही संभव है। इसमें भी औद्योगिक सहयोग की नितांत जरूरत है जैसे पोली-हाउस में उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है लेकिन किसान के पास ना तो संसाधन हैं और ना ही तकनीकी ज्ञान। उद्योग उसके लिए आधारभूत संरचना तैयार कर दें तो उसकी राह आसान हो सकेगी लेकिन यहां प्रश्न फिर भूमि अधिग्रहण के मुद्दे आ अटकता है। किसान को भूमि चाहिए और उद्योग के लिए भी इसलिए दोनों का संतुलन बनाते हुए दोनों पक्षों को न्याय मिलना चाहिए। भूमि अधिग्रहण आसान हो देरी तक मुद्दे लटके नहीं हर किसी नेकदिल इंसान की मंशा है। किसान इसका विरोधी नहीं है लेकिन उसके संसाधनों का भी न्यायोचित मुआवजा मिलना चाहिए जिससे वे अपनी रोजी रोटी से वंचित ना हो तथा उसके आश्रितों को भी मोहताज ना होना पड़े। मुआवजा इतना और इस ढंग से मिले कि उसका भी जीवनयापन सुविधाजनक होता रहे। 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून अंग्रेंज की सहुलियत के लिए बना था जिसमें आमजन की कोई सुनवाई या रूसवाई ना थी। मुआवजा मांगने पर मार या मौत ही मिलती थी। पुर्नवास जैसी कोई बात सोच से दूर थी।

प्रदेशी सरकार की किसान हितैषी मंशा का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बेमौसमी वर्षा व ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक मार से किसानों को गेहूं, चने, सरसों व सब्जियों की फसलें पूर्णतया नष्ट हो गई हैं और प्रदेश सरकारें विशेष गिरदावरी तक नहीं करवा सकी जबकि किसानों को तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। कभी 50 प्रतिशत व कभी 33 प्रतिशत नुकसान पर केवल 10000-12000 राशी देने के खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं जबकि पंजाब, हरियाणा जैसे कृषि सम्पन्न राज्यों में करीब 10 किसान इस बमौसमी वर्षा व ओलावृष्टि से फसलें नष्ट होने पर अपनी जांच गवां चुके हैं और सरकार को केवल भूमि

शेष पेज–2 पर

'k"k i!t &1

अधिग्रहण की चिंता है ना कि अन्नदाता को बचाने की। किसानों में मानसिक रूप भी बढ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रसिद्ध चिकित्सालय में किसान मानसिक रोग से ग्रसत किसान रोगियों करी संख्या में 33 प्रतिशत की बढौतरी हो चुकी है ।

आज भी हालात ज्यों के त्यों ही बने हुए हैं। किसान-काश्तकार के नाम पर केवल शासक बदले हैं, सस्ती राजनीति चमकाई जाती है। सरकार के बेरूखी से परेशान होकर किसान व ग्रामीण वर्ग को शहर की ओर पलायन करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक ने 1996 में सर्वे किया था कि 2005 तक यानि 20 वर्ष बाद भारत में गांवों से शहरों की ओर पलायन करने वालों की संख्या इंग्लैंड, जापान व जर्मनी की जनसंख्या के बराबर होगी जो कि लगभग 20 करोड़ है। एक सोची समझी नीति के तहत किसान को खेती से हटाकर उनकी जमीनों को अधिग्रहित किया जा रहा है जिससे खेती बाड़ी तो खत्म होगी ही किसानी भी स्वत: खत्म हो जाएगी। राष्ट्र में आज 60 करोड़ किसान सर्वाधिक नीचले दर्जे के हैं। नैशनल सैंपल सर्वे आर्गेनाईजेशन की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार एक समस्त किसान परिवार की मासिक आय केवल 3078 रूपये है जबकि शहर में घरों में काम करने वाली एक साधारण महिला 4000 रूपये हर मास कमाती है। आज 58 प्रतिशत किसान मनरेगा जैसी योजनाओं में काम करने को मजबूर हैं और देश का 60 प्रतिशत किसान यानि अन्नदाता भुखे पेट सोता है तथा 42 प्रतिशत किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। आखिर क्या करेगें खेती करके। भारत में 18 सालों में 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं लेकिन किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन जैसे देश में भी भूमि अधिग्रहण की मार से किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। चाईना डेली की एक रिपोर्ट के अनुसार वहां 10 वर्षो में 28 लाख लोगों ने आत्म हत्या की जिनमें करीब 2.20 लाख किसान थे। कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2007-08 से 2010-11 के बीच 20 राज्यों में 7,90,000 हैक्टयर भूमि गैर कृषि कार्यो जैसे भवन निर्माण, उद्योग व अन्य विकास कार्यो के लिए बाहर निकल चुकी है इसलिए आज भूमि अधिग्रहण जैसे किसान विरोधी शिकंजे से किसान काश्तकार को बचाना आवश्यक है नहीं तो किसानी खत्म होने के साथ राष्ट्र में आई हरियाली भी खत्म हो जाएगी।

अब हमें विकसित और विकासशील देशों द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों पर गौर करना होगा तथा उनकी कमियों को दूर कर आगे बढ़ना होगा ताकि राष्ट्र और किसान दोनों का विकास संभव हो सके। महात्मा गांधी जी ने कहा थी असल भारत गांव में बसता है और 86 प्रतिशत लोगों का भरण पोषण कृषि से ही होता है। किसान तो केवल उनके रहमो कर्म पर पीढ़ी दर पीढ़ी पड़ा रहता है। कुछ रूपये का कर्ज कई कई पीढ़ियां चुकाने में असमर्थ थी क्योंकि किसान पढ़ा लिखा ना था उसे अपने हक का आभास तक नहीं था। दीनबंधु सर छोटु राम ऐसे ही परिभेष में उभरे थे। इसीलिए उन्हे किसान के मर्म का पता था तथा वे उसके हक के लिए लड़े और उन्ही की बदौलत कई सारे कानून बने और खेत के लिए पानी की व्यवस्था तथा स्त्रोत तलाशने शुरू हुए।

विनोभा भावे ने भू-दान आंदोलन चलाया ताकि जमींदार अपनी फालतू भूमि इच्छा से दें और किसान वास्तविकता में कृषि अपने तथा परिवार के लिए कर सकें। चीन में हुई प्रगति आज विश्व की नजर में है। यह विकास प्रक्रिया हालांकि 1949 से शुरू हुई थी जब सबसे पहले वहां शहरीकरण ने तेजी पकड़ी। 1949 में वहां केवल 79 शहर थे जो 1981 तक 233 तथा 1995 तक यह संख्या 640 तक पहुंची। वर्ष 1999 तक 667 शहर आबाद हो गए। इस प्रक्रिया में भूमि अधिग्रहण भी तेजी से हुआ और शहीकरण के साथ औद्योगिकरण भी लेकिन किसान का क्या हुआ। उसके अधिकार पूर्णतया नगण्य हो गए। वर्ष 1995 में 812 वर्ग किलोमीटर भूमि अधिग्रहित हुई। कृषि व्यक्तिगत ना होकर सहकारी या सरकारी हो गई। किसान कृषि हेतू भूमि सरकार से किराए पर लेकर कार्य करता है जो 40 से 60 वर्ष तक ही हो सकती है। मुआवजा 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत वार्षिक उत्पादन के बराबर निर्धारित है। समाज, आर्थिक हालात तथा भूमि पर निर्भर लोगों को ध्यान में रखकर पूर्व तीन वर्षो की औसत उत्पादिकता को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय निकास यह राशी 30 गुणा कर सकती है। इसमें किसान की प्रति व्यक्ति आय तक भी समायोजित की जाती है।

लेकिन इस अधिग्रहण प्रक्रिया में खामियां थी क्योंकि मालिकाना हक की ही बात स्पष्ट ना थी। बहुत सी भूमि तो राज्य की ही थी और 1990 तक विकास के नाम पर कोई भी अधिग्रहण कर सकता था। विकास की मद में व्यवसायिक विकास, मनोरंजन, हिरायशी मकान तथा औद्योगिक विकास परियोजना कुछ भी हो सकता है। इसमें राजनेता की नजदीकी भी लाभप्रद होती थी। इससे विकास की धारा तय नहीं होती थी तथा रीयल-एस्टेट में काफी धांधलियां और भ्रष्टाचार हुआ। हाल ही के आर्थिक सुधारों तथा व्यक्तिगत परियोजनाओं को मंजुरी मिलने से राजकीय परियोजनाओं में कमी आई लेकिन इससे भी काफी दिक्कतें महशुस हो रही हैं। राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतू अधिग्रहित भूमि का मुआवजा हर प्रदेश में अलग है जैसा कि राष्ट्रीय गैस परियोजना जो राष्ट्र के पश्चिम से पूर्व तक जाती है, में मुआवजा सरकार ने 20,000 आरएमबी यानि 2500 अमेरिकी डालर प्रति वर्ग गज दिया गया लेकिन किसान को केवल 5000 आरएमबी मिला। अब नई परियोजनाओं हेतू भूमि अधिग्रहण बहुत मुश्किल हो चुका है। भारतीय कम्युनिष्टों के बारे में कहा जाता है कि बीजिंग में बरसात की खबर से कलकता की गलियों में छाते खुल जाते हैं।

यही हालात अब भारत में बनते जा रहे हैं। हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि कोई केस हल ही नहीं होती जब तक यह संभव हो पाता है कि उस परियोजना की दलील ही खत्म हो जाती है। राष्ट्र के 165 जिलों में 252 अधिग्रहण मुद्दे आज भी विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। केवल 15 से 20 प्रतिशत परियोजनाओं को स्वीकृति संभव हो सकी है। इसका सबसे अधिक खामियाजा बैंकों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उन्हे गारंटी में नान-परफारमिंग ईकाईयां लेनी पड़ रही हैं। दूसरे देशों में भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। भूमि अधिग्रहण सरकार का हक है। अमेरिका में एमनेंट डोमेन प्रक्रिया को कंडमनेशन के नाम से जाना जाता है। कनाडा, यु0के0

तथा आस्ट्रेलिया में इसे एक्प्रोप्रिएशन में व्यक्ति÷त संपदा सरकार द्वारा अधिगृहित करना कानूनन जायज है।

भूमि धांधलियों के लिए विख्यात यूपीए सरकार ने हर मुद्दे पर घोटाले किए चाहे वे आदर्श हाउसिंग हो, कायेला खादान हो या वाड्रा के घोटाले एक से बढ़कर एक घपले हुए। राष्ट्रीय संपदा की लूट का कोई मुद्दा घपले से अछूता ना रहा। कुदरती स्त्रोतों की लूट में केाई कोर कसर बाकी ना छोड़ी। किसान हित के नाम पर 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल भी पारित करवा दिया ताकि आगामी सरकार विकास के नाम पर कुछ कर ही ना सके। इस बिल में अधिग्रहित भूमि के 80 प्रतिशत मालिकों की मंजूरी जरूरी है जो ऐसी ही है – 'ना नौ मन तेल ना राधा नाचेगी।'

अब एक बिल लोकसभा से पारित हो चुका है और राज्य सभा में पारित होना बाकी है। 2013 के बिल 1894 के कानून की बदली है। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व आंकलन से पूर्व संसद की अधिसूचना जरूरी है। मुआवजा राशी देहाती भूमि हेतू मार्केट कीमत का चार मुणा तथा शहरी भूमि में दो गुणा के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें अधिग्रहण भूमि के 80 प्रतिशत मालिकों की मंजूरी जरूरी होगी। यह बिल 16 अधिसूचनाओं के तहत चल रही परियोजनाओं जैसा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 1989 इत्यादि में प्रभावी नहीं होगा लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कृषि भूमि अधिग्रहण विस्थापित पुर्नवास में सांसद की क्या भूमिका रहेगी। दूसरे सरकारी इरादों हेतू अधिग्रहण के मुद्दे पर 80 प्रतिशत विस्थापितों या मालिकों की मंजूरी की शर्त नहीं है। देहाती भूमि में चार गुणा तथा शहरी में दो गुणा की मद अप्रभावी होगी क्योंकि रजिस्ट्री अक्सर कम मूल्य पर होती है। सरकार तीन वर्ष तक भूमि अधिगहण कर सकती है इसमें पुर्नवास की शर्त भी नहीं है।

वर्तमान में लोकसभा द्वारा पारित बिल में भर्त्सना हो रही है क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि इससे मुजारे को मुआवजा नहीं मिलगा जो अक्सर भूमि को जोत रहा है लेकिन मालिक नहीं है। इसके विरूद्ध विपक्ष के साथ-साथ अन्ना हजारे ने भी हाथ मिला लिया है। इसमें 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की मद पूर्णतया हटा दी गई है।

सरकार ने 2013 के बिल की धारा 10ए को बढ़ाकर पांच सैक्टर और जोड़े हैं। यहां सहमति का अधिनियम प्रभावी नहीं होगा। जिसमें व्यक्तिगत कंपनियों को 80 प्रतिशत सहमति की शर्त नहीं होगी। सहमति तथा सामाजिक आंकलन-राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा बलों, सेना, देहाती मूलभूत संरचना, विद्युत परियोजनाएं, औद्योगिक गलियारे तथा गरीबों हेतू मकान एवं सरकारी स्वामीत्व वाले पीपीपी मुद्दों में सहमति की धारा प्रभावी नहीं होगी। नए बिल में केवल मालिक को मुआवजा मिलेगा ना कि उसके आश्रितों को भी। उपरोक्त पांचों मुद्दों पर अधिग्रहण में भूमि उर्वरता या अउर्वरता का ध्यान भी नहीं रख जाएगा।

किसान के हित में इस अधिनियम में पूर्व बिल के 13 संशोधनों को शामिल किया गया। यहां मुआवजा लागू रहेगा जिसमें पूर्व में पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना की एकाग्र केंद्रीय नीति नहीं है। इनमें कोयला क्षेत्र अधिग्रहण तथा विकास अधिनियम 1957, राष्ट्रीय मा÷ अधिनियम 1956, खादान अधिनियम 1885, पुरात्व व पुरातन महत्ता की परियोजनाएं व क्षेत्र अधिनियम 1948, विद्युत अधिनियम 2003, अचल संपदा अधिनियम 1952,पुनर्वास अधिनियम 1948 तथा मैट्रो रेल अधिनियम 1978 भी इनमें शामिल कर लिए गए हैं। इन मुद्दों पर किसानों के पुनर्वास तथा मुआवजा राशी भी अधिक दी जाएगी। मुआवजा राशी वही देहाती भूमि का चार गुणा तथा शहरी भूमि का दो गुणा ही रहेगा। पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य श्री एन सी सक्सैना ने इस बिल की सराहना करते हुए कहा है कि पूर्व बिल किसान तथा उद्योग दोनों के विरोधी था। इससे किसान तथा उद्योगपति वर्षो तक न्यायिक प्रक्रिया में उलझे रहते और निर्णय किसी के पक्ष में भी ना हो पाता। वर्तमान में इस समस्या का कुछ हद तक हल निकालने का प्रयास किया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली के अनुसार धारा 105 में स्पष्टता लाना जरूरी था जो जनवरी 2015 से पूर्व करना नितांत आवश्यक था। अगर भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाता तो निवेशकों को यह संदेश कभी नहीं दिया जा सकता कि लाल फीताशाही हटा दी गई है। इससे 'मेक इन इंडिया' को साकार करना संभव होगा। कांग्रेस के विपक्ष में हरियाणा तथा केरल सहमति की मद हटाने तथा पीपीपी में 50 प्रतिशत करने के हक में हैं।

सामाजिक प्रतिष्ठा आंकलन मुद्दे पर कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा मणीपुर राज्य इसे केवल बड़ी परियोजनाओं तक सीमित रखने के पक्षधर हैं। दोनों सदनों में बिल पारित होने की स्थिति में गरीब का हित सुरक्षित रखने की सरकारी मंशी आंकी जा रही है। स्वामी नाथन रिपोर्ट लागू करने का वक्त आ गया है जब यूरोप कर सकता है तो भारत जैसा विशाल देश क्यों नहीं?

प्रत्येक राज्य में गुजरात की तरह (सीईपीटी) तथा टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए। किसानों को विकसित भूमि रेट का 10 प्रतिशत मिले। विस्थापितों को कल-कारखानों में नौकरी, परिवार के सदस्य को 2 से 5 वर्ष तक का निशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण, अधिग्रहित भूमि देहात में स्कूल, हस्पताल, पक्की गलियों, सामुदायिक केंद्र, शुलभ शौचालय तथा देहात हितैषी परियोजनाएं उद्योगों द्वारा प्रावधान करना चाहिए ताकि राष्ट्र की प्रगति में भी बाधा ना आए और किसान भी अपना जीवन यापन सुख सुविधा से यापन कर सके और यह फक्कीर अपना आदत के अनुसार सबके लिए सदाएं देते रहें। वर्तमान में तो राष्ट के किसानों का भाग्य पूर्णतया दोनों सदनों की इच्छा पर निर्भर है क्योंकि सर्वोच्च न्यायलय ने भी 13 अप्रैल 2015 को भारतीय भूमि अधिग्रहण अध्यादेश संसोधन 2015 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

डा0महेन्द्र सिंह मलिक
आई0पी0एस0(सेवा निवृत)
पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य चौकसी ब्यूरौ प्रमुख, हरियाणा
प्रधान, जाट सभा चंडीगढ़ / पंचकुला एवं
अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति

HAS NARENDRA MODI BECOME A FADING STAR?

- R.N. Malik

The performance of Shri Narendra Modi as the new Prime Minister of India was judged twice in the past when he completed a span of 100 and 200 days of his incumbency. But the people at large ignored his average report card because a period of 100 or 200 days was considered too short to judge the performance of a Prime Minister. Now the PM will be completing the first year of his five years term on 26th May 2015. Now one year is a sufficient period to correctly asses his performance and competency.

Dr Manmohan Singh had become the whipping boy for his very poor performance as PM during his second term because of naked corruption in the Ministries, sloth , hubris , poor governance, crass negligence of infrastructure development and passage of two retrograde Bills .i.e. Food Security Act and Land Acquisition Amendment Act. BJP acquiesced to the passage of these two Bills for fear of political reprisals as these were introduced at the fag end of the last session of the Parliament.

In such a dismal scenario, Shri Narendra Modi strode on the political horizon like a colossus in September 2013. He had already acquired the image of a radical game changer during his incumbency as Chief Minister of Gujarat for three terms, though the State could claim credit to occupy number one position in India only in respect of ensuring 24 hours supplies of water and electricity. All other important parameters of governance like sanitation or public health in Gujarat were below par. But he conducted his election campaign on professional lines by engaging top class image building agencies and spending party funds very lavishly. The pitch of his election campaign was development, development and development. People desperately wanted a change and saw in Narendra Modi a PHOENIX like hero who could bring economic prosperity on an accelerated scale. Accordingly they voted for him (and not BJP) overwhelmingly. Consequently, BJP got absolute majority for the first time by begging 282 seats and NDA got 334. Narendra Modi took the oath of the office of the Prime Minister on 26/5/2015 with great fanfare and showbiz.

Soon after, the people in general and youth in particular started looking towards Narendra Modi with bated breath to initiate his radical development agenda that would provide employment opportunities to the vast army of (aspirational , transactional , desperate and unforgiving) youths and revive the economy to its pristine level of 10% of GDP growth. But nothing of this kind happened during the first one year of his rule. The first and foremost job of a good Prime Minister is always to delineate the road map for economic development and present it before the nation as a confidence building measure. The PM did not discharge this essential duty at all. He did not call even a single meeting of State Chief Ministers to ascertain their views on reviving the economy of the states and the country and fix the targets. To make matters worse , he scrapped the Planning Commission (considering it as a relic of Nehruvian philosophy) and replaced it with an effete organisation, called NITI Ayog. Nobody knows till now what this Ayog is doing and what is its mandate.

However the PM limited his development agenda to the following ten decisions to bring the Achhe Din.

1) Launching the half - baked Swachh Bharat Abhiyan. It was a wonderful program. Had it been designed and implemented on professional lines, it would have changed the sanitary face of India and upgraded the human development index. But now nobody talks of this program anymore and it is almost dumped in the dustbin of history.

2) Launching Ganga Cleaning Project. This program is being taken up very seriously because of the directions of the Supreme Court.

3) Scaled up the targets of developing renewable energy to 1.75 lakh MW by 2022 (Solar =1.0 lakh MW, Wind = 0.6 lakh MW, Biomass=0.1.MW and Micro hydel=0.05 lakh MW) . This program can definitely bring an investment of Rs.15.0 lakh crore during next 6 years and desert areas of many states would get a big economic boost.

4) Mr Piyush Goyal , the Minister for Power and Coal has set the target of mining 1.0 billion tons of coal per year by 2019.How he will be able to achieve this difficult target has not been explained so far.

5) The Financial Budget was a bit reformist. But the basic problem of NPAs and rising debts on States remained untouched. The Railway budget promised for doubling and electrifying Railway tracks by 2019 costing Rs. 170 lakh crore. But the honourable minister has not spelt out the methodology to arrange this huge sum of money so far. Presently Indian Railways (IR) is struggling and surviving below the poverty line and the Minister did not show the guts to increase the fares to bring it above the line.

6) The PM visited USA and Japan to attract foreign investment last year. Now he has gone to France, Germany and Canada for the same purpose. Nothing has materialised so far. Foreign investors do not come for the asking or by sending them invitation cards. They will come only if well designed industrial estates are developed near the port cities and the parameter of " Ease of doing business in India" is improved simultaneously. Unfortunately nothing has been done so far in respect of these two essential parameters .However the PM has floated a new idea of " Make in India" asking the exporting countries to set up their manufacturing units in India particularly in the field of Defence Production. Airbus industry of France has promised to invest $2 billion. The PM is very passionate about the success of this program and let us hope that he succeeds in his mission. It will be a big leap forward to change the economic scenario in the manufacturing sector.

7) The PM piloted a Bill to amend the existing Land Acquisition Act 2013 to facilitate the acquisition of land for infrastructure projects by removing the provision for seeking consents from 70% farmers. It was a bold move but the PM could not address the objections of the Opposition parties in the Parliamentary debate in an articulated manner and the Bill could not be passed in the Rajya Sabha. Consequently the amendment was implemented through the Ordinance route and the same

has now been challenged in the Supreme Court. This in articulation created lot of misgivings in the minds of farmers and the Opposition parties have launched a strong disinformation campaign against the Bill. In fact the moribund Congress party has got a fresh lease of life only because of this reason. Now the Modi Government is touted as pro-capitalist and anti -farmers. This perception will take a long time to go away.

8) The PM had floated a novel project of development of one village by each MP in his constituency. This program too has flopped miserably because of non availability of funds and lack of interest exhibited by the respective MPs.

9) The auctioning of coal blocks and spectrum (credit for this goes to CAG , Supreme Court and the man who filed the PIL) will fetch lacs of crore rupees. The auction amount of coal blocks will mostly go to states where coal blocks are located. The amount is sufficient enough to pay the debt of those states and close the gap of fiscal deficit.

10) The Financial Budget provides for setting up five ultra modern power plants (UMPP) of 4000 MW each. UMPPs allotted a decade earlier (except one of TATA's) have not been commissioned so far.

This 10 point program of the PM failed to enthuse and inspire confidence in the public for want of a ballistic or big-bang or a radical development agenda which could generate enough employment opportunities for the youths. The promise of Achhe Din is still haunting the voters. The main grouse of the people is that not even one big ticket project has been initiated so far and the Prime Minister only talks too much. On the other hand, the PM also failed to captain the team of State Chief Ministers who are still running the states in a feudalistic and confiscatory manner and treating the States as their personal fiefs. People are now fed up with the ways the emoluments of the MLA's and Ministers are being enhanced and the way CM's are using the State funds and resources in a profligate manner. Finally the ire of the people against the Modi government burst out in the general election of Delhi Vidhan Sabha in Feb 2015 where BJP got only three seats out of a total of 70. It was the most shameful defeat for a ruling party barely nine months after coming into power at the Centre.

Now the media is criticizing the PM more for his silence on insidious remarks or diatribes of BJP leaders like Giriraj Singh from time to time than palpable failure on infrastructure front. Lethargy in taking up big ticket infrastructure projects is more pernicious than the saffronisation issue. Accordingly people in general and youth in particular have started believing that the PM is behaving like a novice or a naive politician who does not know what to do and the bureaucracy is not advising him properly. The two recent budgets i.e. Railways and Finance budgets lacked clarity and promise for 10 % growth in GDP and eradication of poverty. A critical analysis of one year incumbency shows that PM is relying on only one thumb rule for economic development of the country i.e. attracting foreign investment through the Make-In-India program so that the country does not have to import large categories of machinery and equipments. This effort no doubt is praise worthy but it alone cannot revolutionise the national economy or be a panacea of all the economic problems plaguing the country. In fact what really saved the situation for the government is the crashing of crude oil prices to $45 per barrel which in turn cut down the inflation and the RBI further cut down the interest rates. This favourable tail wind brought the much needed relief in the national economy. It reduced the import bill of crude oil by half and eased the position of forex and reduced the gap in Current Account Deficit. Otherwise the economic scenario would have been extremely depressing. Notwithstanding this fact, recession stays as it is. The export earnings are dwindling. This lack-lustre performance of the government is causing a great concern to those who had anticipated a bright future for the country after the coronation of Narendra Modi as the new Prime Minister of India. Consequently his dare-devil or development savvy image has taken a severe beating. Last year he was dubbed as the Rising Sun of the East or Crescent Moon of the West or the twinkling star of the sky. Now his position represents a fading star.

Only time will tell (the next year is the most crucial year) whether he will take the wake up call from the media reports and rework his strategy or not. The hard fact of the matter is that economic problems facing the country are so vast and deep rooted that only a person of the vision and ilk of Den Xiaoping or Margaret Thatcher or Le Kuan yew or Sardar Patel can take the country out of the mess. Till now Mr. Narendra Modi has not been following the footsteps of any one of them.Mere pious speeches or rhetorics or coining development slogans and governance acronyms will not work now. People will be enthused only with the launching of big ticket infrastructure projects like the six- lane Express -way from NOIDA to Balia initiated by Mayawati Government or Delhi Metro Project. Now the common cat- call is "If elections are held today, the country will become BJP Mukt Bharat". It does not require much of brain storming to find the way out. Timely implementation of following ten point program can catapult the country into the comity of developed nations.

1) Drastic control of population 2. Improving standards in educational institutions (both private and government) 3. Solar and Sanitary revolution in the country 4. Development of Indian Railways as new engine of growth 5. Improving the service delivery of existing infrastructure and get rid of loss making undertakings (both public and private sectors). 6.Developing infrastructure projects (expressways, hydro power plants etc) on an aggressive scale and development of 50 new townships to act as sub-capitals in bigger states and also to decongest the bigger cities of India 7. Extend irrigation facilities in whole of Central India 8. Launching Dairy Development and Horticulture projects in 7 NE-states 9. Improving exports of iron ore and other minerals 10. Developing modern industrial parks along coastal areas and aggressive development of oil and gas resources in Rajasthan.

There is no other short-cut to achieve the target of 10% growth in GDP and eradicate poverty except to implement the aforesaid 10 point program. The only moto of the Government should be," To beat China in the economic race by 2025". That is all the required to do. Once the progress starts on an even keel, a feel -good factor - or a buoyant mood will be developed in whole of the country and the country will start progressing by leaps and bounds. The fast development process will drive away the communal clouds automatically as well. But think over - what will happen if the PM does not take up the wake up call now!

''चार पीढ़ियों से फौज में''

& duy ihjFkh flg

रोहतक के गाँव रिठाल का एक जाट परिवार पिछले 150 साल से फौज में नौकरी करता आ रहा है जिसकी अब चौथी पीढ़ी फौज में है। कर्नल निर्भय सिंह रिटायर होने के बाद सैक्टर 21 पंचकूला में बस गये हैं। उनके दादा के बड़े भाई सुबेदार जुगलाल 1868 में 14 मौरी जाट लान्सर में भर्ती हुये थे। उन दिनों फौज में भर्ती होने के लिए अच्छे कद काठी के साथ खुद का घोड़ा होना जरूरी था सुबेदार जुगलाल ने घर से घोड़ा लिया और भर्ती हो गये। इन्होनें 1878 में काबुल करी दूसरी लड़ाई में हिस्सा लिया था। यह वही बहादुर जाट पल्टन थी जो अफगानिस्तान में गजनी को फतेह करके वहां से सोमनाथ मन्दिर की चौखट व किवाड़ वापिस लाई थी जो मोहम्द गजनी लुट कर ले गया था। सुबेदार जुगलाल का छोटा भाई जयलाल जो कर्नल निर्भय सिंह का दादा था वो भी 1895 में 6 जाट पलटन में भर्ती हो गया। अंग्रेज कमाण्डरों को जाटो की एक बात बहुत पसन्द थी कि उनकी स्पष्टवादिता व लड़ाई के मैदान में अपनी जान पर खेल कर दुश्मन को उसके मोर्चे में घुस कर मारना। जाट हमेशा बहादुर व सख्त कमाण्डर की इज्जत करते थे। कमजोर कमाण्डर जाटों से इज्जत पाने में नाकाम रहे हैं। उन दिनों जाट कभी पैसों के लिए भर्ती नहीं होते थे। उनको फौजी वर्दी पहनने का शौक तथा जंग के मैदान में जान पर खेलकर दुश्मन से दो–दो हाथ करने में मजा आता था जनरल सर जौहन इरर्कन मुरी के.बी.सी. जिसने 1857 में 14 मौरी लान्सर खड़ी की थी उसको जाटों से इतना प्यार था कि उसने अपनी सारी जायदाद जाटों के नाम कर दी थी। यमुना घाट दिल्ली लाल किले की तरफ जाटों की सबसे पुरानी धर्मशाला है जो इसी जनरल ने बनाई थी। 1914 में जब पहला महायुद्ध शुरू हुआ और जर्मन फौजे तुफान कि गति से फ्रांस व इंग्लैड कि तरफ बढ़ रही थी तो हिन्दुस्तान से इसी 6 जाट पलटन को फ्रांस के मोर्चे पर भेजा गया। वहां एक बहुत ही खुनी लड़ाई लड़ी गई जो बैटल ऑफ वैली चैपल के नाम से अभी भी मशहुर है। जाटों ने न सिर्फ जर्मनों को आगे बढ़ने से रोका बल्कि उनके कई मोर्चे छीन लिए। जर्मन जब भी जाटों का लड़ाई का नारा ''जाट बलवान जय भगवान'' सुनते तो अपने आप डिफंन्स मोर्चे में पोजीशन ले लेते थे। इस लड़ाई में 6 जाट रेजिमेन्ट के 70 प्रतिशत जवान मारे गये थे या जख्मी हो गये थे। 19 दिसम्बर 1914 रात को इस लड़ाई में एक जर्मन मशीनगन पोस्ट जाटों का आगे बढ़ने का रास्ता रोके हुए थी। हवलदार मैजर जयलाल पैट के बल रेंग कर उस पोस्ट तक पंहुच गये तथा बैनट की गुत्थम–गुत्थी की लड़ाई में जर्मन के चार जवानों को मार कर मशीनगन पोस्ट पर कब्जा कर तथा गन का मुंह दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया तथा खुद भी मारे गये। उनकी इस दिलेरी व बहादुरी पर उनको सबसे बड़ा बहादुरी का मैडल ''इंडियन आर्डर ऑफ मैरिट'' दिया गया जो उस समय 'विक्टोरिया क्रॉस' के बराबर था। अभी तक 'विक्टोरिया क्रॉस' केवल अंग्रेजो को ही दिया जाता था। क्योंकि अंग्रेज सोचते थे कि उन्ही की कौम बहादुर है। परन्तु जाट रणबांकुरो में तो शेर जैसा दिल होता है और अंग्रेजो को मानना पड़ा की जाट गौरों से 19 नहीं बल्कि 20 है। जब जाट लगातार अपनी जान पर खेल करबहादुरी के झण्डें गाड़ते रहे तो अंग्रेजों ने मजबुर होकर हिन्दुस्तानियों को भी 'विक्टोरिया क्रॉस' देना शुरू कर दिया। सबसे पहले किसी हिन्दुस्तानी को 'विक्टोरिया क्रॉस' 1916 में दिया गया। यह भी एक जाट रणबांकुरा था रिसालदार बदलु राम गांव ढाकला जिला रोहतक का था जो एक दूसरे मोर्चे पर जान पर खेलकर शहीद हुए थे। उन दिनों गांव कि औरते गीत गाती थी।

1. उन बिरा के जिना–जिनके बालम 6 नम्बर में (यानी 6 जाट पलटल में)।
2. बिरा तू भर्ती हौन चाल पड़ा मेरा कोन भरेगा भात, बैबे तू मत घबराइये हे, तेरा आन भरूगा भात। क्योंकि भर्ती होते ही ट्रेनिंग देकर सीधे पानी के जहाज से जर्मन मोर्चा पर भेज देते थे और वहां से जिन्दा वापिस कम ही आते थे। यह लड़ाई 5 साल चली थी।
3. हवलदार मैजर जयलाल को मैडल के अलावा 2 मुरबे जमीन भी ईनाम में दी गई थी। इनकी फोटो व मैडल तथा बहादुरी की शोर्य गाथा जाट हिरोज मयुजियम बरेली में सुसोभित है। जाट रेजीमेन्ट सेन्टर बरेली में जाटों का मयुजियम है। वहां जिसने लड़ाई के मैदान में सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाई उनका जाट रोल ऑफ ओनर बनाया गया है जिसमें ऊपर से तीसरे नम्बर पर हवलदार मैजर जयलाल का नाम लिखा हुआ है। इस बहादुर की विधवा उनके शहीद होने के 15 साल तक जिन्दा रही। महारानी, इंग्लैंड व वाइसराई ऑफ इण्डिया चैम्पसफोर्ड ने इनको

सनद व स्पैशली प्रशंसा पत्र भेजा था। वह जब तक विधवा होकर जिन्दा रही कभी खाट पर नहीं सोई व जमीन पर गुदड़ा बिछा कर सोती थी तथा दिन में पीढ़े पर बैठ जाती थी।..... चौधरी छोटू राम को जब इस जाट परिवार व बहादुर औरत का पता चला तो वे रिठाल गांव पंहुचे और इनकी हवेली में बहादुर बुढ़िया के हाथ से दुध पिया।

इण्डिया गेट दिल्ली में जहां 24 घण्टे अमर ज्योति जलती है और 26 जनवरी को परेड से पहले प्रधान मंत्री व तीनों सेना के चीफ अपनी श्रद्धा प्रकट करते है यह इण्डिया गेट अंग्रेजों ने उन चुने हुए जाट दुसरे बहादुर फौजियों की यादगार में बनाया था जिन्होंने 1914 से 1919 के महायुद्ध में सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाई थी। हवलदार मैजर जयलाल का नाम भी दुसरे बहादुर फौजियों के साथ इण्डिया गेट पर लिखा हुआ है।

हवलदार मैजर जयलाल का बड़ा लड़का कर्नल बिजे सिंह 1933 में फौज में भर्ती हुए तथा 1966 में रिटायर होकर रोहतक में बस गये। उनका पौता मैजर डॉक्टर ईशवर सिंह रोहतक में ओथोपेडिक्स का जाना पहचाना नाम है। हवलदार मैजर का दुसरा लड़का रतन सिंह मौन्टगोमरी (अब पाकिस्तान में) ईनाम में मिली मुरबे कि जमीन की देखभाल तथा वह लम्बरदार व जैलदार रहा है। रतन सिंह लम्बरदार ने चौधरी छोटूराम की जमीदारा पार्टी व जाट गजट अखबार में किसानों की भलाई के काम में तथा जाट कौम से 1939 की लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा जाट जवानों को भर्ती कराने के काम से चौधरी छोटूराम ने खुश होकर एक मुरबा जमीन दी थी जो अभी भी इस परिवार के पास है। 1947 में जब देश आजाद हुआ और पाकिस्तान बना तो रिठाल गांव के पास काहनी गांव जो मुसलमानों का गांव था वहां जमीन अलाट हो गई। रतन सिंह का लड़का कर्नल निर्भय सिंह 1968 में फौज में भर्ती हो गया तथा 1971 की लड़ाई में लौंगेवाला सैक्टर में राजस्थान बॉर्डर पर जहां पाकिस्तान की पूरी टैंक बिग्रेड तबाह कर दी गई थी तथा जिस पर बॉर्डर फिल्म भी बनी है उस लड़ाई में हिस्सा लिया तथा बहादुरी के लिए मैनसन इन डिस्पैच का मैडल मिला। कारगिल की लड़ाई में भी बाल्टीक मोर्चे पर तैनात थे। 2002 में रिटायर होने के बाद पंचकूला सैक्टर 21 में बस गये तथा जाट सभा की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते है। इन्होनें अपने गांव व गुहांड के 18 जवानों को फौज में भर्ती करवाया तथा अब भी रिटायरमेन्ट होने के बाद अपनी सिक्योरिटी कम्पनी के तहत बहुत बेरोजगार जाट लड़कों व रिटायर फौजियों को गनमैन व गार्ड की नौकरी दिलवा रहे हैं।

कर्नल निर्भय सिंह के दो बच्चे है तथा दोनों फौज में है। लड़की की नेवी ऑफिसर से शादी की है जो खुद भी नैवी में कर्नल हैं तथा लड़का मेजर नवीन मकेनिकल इंजीनियर है। वह भी किसी मल्टी नैशनल कम्पनी में जाने की बजाय अपनी खानदानी जज्बा रखते हुये 2002 में फौज में भर्ती हो गया। मेजर नवीन आजकल कश्मीर में तैनात है। कर्नल निर्भय सिंह का कहना है कि जाटों का फौज में जाना स्वभाविक है यह तो हर जाट के खून में होता है। किसी भी लड़ाई का इतिहास उठाकर देख ले सबसे ज्यादा शहादत जान की कुर्बानी जाटों के खून की मिलेगी, कर्नल निर्भय सिंह तो अपने पौते को भी फौज में भेजने कि ख्वाईश रखते है।

"सुख ना जाये ये पौधा आजादी का–सींच रहे हैं हम अपने खून से"
जाटों के ऐसे ही सपूतों के बुते पर शौर्य के किस्से मशहुर है हमें उनकी इस सोच व देश भक्ति की भावना पर हमें गर्व है।

समझदार अनपढ़

jkgh] t ; iqj

अब उनकी समझ को तो ^lyke* ही किया जा सकता है जो मानते हैं कि इस देश के अपनढ़ लोग मूर्ख होते हैं और दसवीं पास करते हर आदमी के सुरखाब के पर निकल आते हैं। th ughA साक्षरता और समझदारी का कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर आपके पास हमारे संग दो चार दिन बिताने का वक्त हो तो हम आपको उदारहण देकर बता सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। अब यह सत्य है किताबें इंसान के दिमाग की खिड़कियां खोलती है। और जिस कमरें में जितनी ज्यादा खिड़कियां होती हैं उसमें उतना ही प्रकाश और ताजी हवा भीतर आती है। पर भाई साहब! तेज तूफान और चिलचिलाती धूप में खिड़कियां बंद भी करनी पड़ती हैं। अब हम तो अपनी बूढ़ी नानी की ही बात करें। उसके लिये काला अक्षर भैंस बराबर थी लेकिन सारा मोहल्ला सलाह मशविरे के लिए उनके पास आता था। जब मामा घर का खर्चा चलाते तो पूरा न पड़ता लेकिन जब तक नानी के हाथ में गृहस्थी का वित्त मंत्रालय रहा तब तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। सजी नाते रिश्तेदार तो क्या, कस्बे भर के लोग शादी ब्याह के मामले में नानी से राय लेने आते थे। आज भी लोग हमारी नानी जैसी समझदार डोकरियां गांव–गांव, ढ़ाणी–ढ़ाणी में भरी पड़ी हैं। नानी ने कभी फिल्म नहीं देखी लेकिन सहज बुद्धि फिल्म ^ihd* के एलियन से भी ज्यादा मौलिक थी।

अब जरा व्यापार के क्षेत्र में नजर डालिए। उन्नसवीं सदी में मरू भूमि से सैकड़ों व्यापारी तिजारत के लिए हिन्दुस्तान के कोने–कोने में गए और चालीस–पचास बरस में देश के बड़े व्यापार और उद्योगपति बने। उन्होंने किस विश्वविद्यालय से 'एमबीए' किया था, धीरू भाई अंबानी के पास कौन सी मास्टर्स डिग्री थी। राजनीति में एक नहीं हजारों नेता ऐसे मिल जाएगें जो कि लगभग अपनढ़ थे लेकिन जनता के दुःख–दर्द को समझने में उन्हें महारत हासिल भी। उनके मूल सवालों के सामने कई फन्ने खां प्रशासनिक अधिकारी बगलें झांकते नजर आते थे। और पढ़े लिखें ने इस देश की क्या दुर्गति की है वह सब आपके सामने है।

सरकारी उद्योग संस्थानों को तो बड़े–बड़े पढ़े लिखे अफसर ही चलाते हैं न फिर ये 'संस्थान' काहे को करोड़ों के घाटे में ही चलाते हैं न फिर ये ^lLFkku* काहे को करोड़ों के घाटे में ही चलते रहते हैं? अब सरकार की तो सरकार जाने पर साहब हम तो अपनी सहज बुद्धि से इतना जानते हैं कि इस देश का जितना कबाड़ा पढ़े लिखों ने किया है उतना अनपढ़ों ने नहीं किया। अजी इसका मतलब यह न लगा लेना कि हम पढ़ाई लिखाई के खिलाफ हैं। हमारी तो दाल रोटी ही लिखने पढ़ने से चलती है पर ये न पूछना कि हमारे पास कौन सी ^fMxzh* है। तुलसी, कबीर, गालिब, टोडरमल, अकबर ने किस बोर्ड से मैट्रिक की थी? किसी को पता है।?

धर्म स्थल पर वस्त्र संयम

HkjpUn tSu] ckMesj

भारतीय संस्कृति में धार्मिक स्थल सदैव दर्शनीय, पूजनीय, वन्दनीय होने के साथ–साथ आदरणीय रहे हैं। जिसके प्रति निष्ठा, भक्ति स्वतः ही उमड़ती रही है। जन समुदाय इसके मान सम्मान को रखने के लिए सदैव कटिबद्ध रहता है। धार्मिक देव स्थलों के अतिरिक्त सभी महात्माओं के साधना एवं भक्ति स्थलों को भी पवित्र एवं पूजनीय माना जाता है। जहां जनमानस श्रद्धा से भक्ति, आराध ाना, उपासना, तपस्या आदि कई प्रकार की साधनाएं कर अपनी आत्मशुद्धि के साथ कर्मों की निर्जरा अर्थात बुरे कर्मों को मिटाने के लिए प्रयत्नशील रहता हैं। इस कारण सभी धर्मों के धार्मिक स्थल पवित्र एवं पूजनीय बने रहते है। इनकी अवहेलना, आलोचना, तिरस्कार, आसातना आदि नहीं हो इसका प्रत्येक धर्मावलम्बी पूरा ध्यान रखता है। यदि कोई भी किसी धर्म के धार्मिक स्थल की पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास एवं प्रयत्न करता है तो उसे नास्तिक कहा जाता है साथ ही वह दंड का भागीदार भी होता है। भारतीय संस्कृति में धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाये रखने के लिए पूरा ध्यान रखा जाता है, ताकि ये वासना, कामुकता, व्यवसाय आदि के स्थल नहीं बने। इसके लिये इनके दर्शन करने आने वाले सभी लोग संयम एवं सादगी के साथ सहिष्णुता, समभाव, स्नेह रखते रहे। लेकिन आजकल की पाश्चत्या सभ्यता ने हमारे धार्मिक स्थलों को श्रद्धा भक्ति के स्थान पर काम वासना के वातावरण में डूबो दिया है। इसके पीछे दोष है वस्त्र पहनावा। जो पारदर्शी होकर नग्नता को प्रदर्शित करने लगा है। इस कारण धार्मिक स्थलों का वातावरण अब धर्ममय नहीं रह कर मनोरजंन व वासनाओं का साधन बनता जा रहा है।

अक्सर देव स्थलों, मन्दिर, मठों आदि के दर्शन करने आने वाले दर्शकों में पुरूष की अपेक्षा महिलाएं अधिक आती हैं। जिनका धर्म के प्रति अधिक श्रद्धा, भक्ति, आस्था रहती है। लेकिन आजकल महिलाओं का पहनावा अर्धनग्न सा हो गया है। वे अपने वक्ष स्थलों को ढकने की बजाय उसे कम वस्त्रों से छिपाने का प्रयास करती है। कुछ महिलाएं जिसमें जवान बालिकाओं ने तो उस पर पल्लू रखना छोड़ दिया है। इस खुली नग्न अवस्था को देखकर सभ्य एवं समझदार व्यक्ति तो शर्मसार हो जाता है लेकिन बालिकाऐं इस प्रकार से अब प्रदर्शन करने में अपनी शान समझती है। जो कामुकता को आमंत्रित करती है। जवान बालिकाओं ने शरीर के ऊपरी भाग पर वरूत्र रखना प्रायः छोड़–सा दिया है और पुरूषों के पहनने वाले बनियान, टी–शर्ट आदि को शान एवं शौक से पहनने लगी है। जिसके कारण उनके उभरे वक्षस्थल पुरूषों को कामुक भावना से प्रेरित करते हैं। जिसके कारण बालिकाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार आदि की अशोभनीय, अप्रिय, अमानुषिक घटनाऐं घटित होने लगी है। ऐसे वस्त्र पहन कर अक्सर बालिकाओं, जवान महिलाओं के झुण्ड के झुण्ड धार्मिक देव स्थलों, साधना स्थलों पर धार्मिक आस्था का दिखावा करने के लिए मंडराते रहते हैं। जिसे देखकर धर्मगुरूओं के साथ आम नागरिक भी विचलित होकर वासना के शिकार हो जाते हैं। इससे धार्मिक स्थलों की पवित्रता को आंच आती है वहां धर्म गुरूओं की साधना भी खंडित होकर देर सवेर बदनामी का कारण बन जाती है। महिलाऐं, जवान व किशोर बालिकाऐं अपने शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाले वस्त्रों को संयम रखने के साथ नीचे पहने जाने वस्त्रों का भी लज्जा छुपाने के लिए बराबर ख्याल नहीं रखती है। यदि कभी इन्हें बन्दन करने, नमन करने आदि के लिए झुकना पड़ता है तब ऊपरी भाग जो वस्त्र रहित होता है उसका प्रदर्शन अच्छे से अच्छे इन्सान को कामुक भावना से कामुक बना देता है। जो धार्मिक स्थलों की मर्यादाओं को धर्म गुरूओं की साधना को मटियामेल कर देता है। साधारण पुरूष दर्शक भी ऐसे नग्न दृश्य देखकर प्रभु दर्शन को भूल बैठता है और उसका मन कामुक भावनाओं में डूब जाता है।

धार्मिक साधना स्थलों पर महिलाओं, जवान एवं किशोर बालिकाओं को वस्त्र पहनने का संयम बरतना चाहिये। जिससे उनके लज्जा वाले अंगों का खुला प्रदर्शन नहीं हो। इसके अतिरिक्त शरीर पर पूरे वस्त्र पहने ताकि अंग खुले ना हो। यही तो स्त्री की लज्जा है। जहां वस्त्र संयम रहेगा वहां कामवासना का वातावरण नहीं बन पायेगा। अक्सर स्त्री ने वस्त्र मर्यादा छोड़ी है तब उनके जवान अंगों की तरफ आकर्षित होकर संसार त्यागी संत महात्माओं ने स्त्री की कामवासना से प्रेरित होकर पुनः संसारिक जीवन को अंगकार कर जन आक्रोश एवं जनभेदनी की आलोचना का शिकार हुए हैं। यदि हमारी बहन, बेटियों, बहुएं पाश्चात्य वस्त्र सभ्यता की अधीन रही तो हमारे धार्मिक स्थलों को वासना के केन्द्र बनते देर नहीं लगेगी इस प्रकार के कई समाचार, समाचार–पत्रों की सुर्खियों में भी रहे हैं।

स्त्री की लज्जा को ढकने के लिए वस्त्र ही सब कुछ है। वस्त्रों का पहनावा संयम एवं मर्यादा पुर्वक होना चाहिये। वहां ध ार्मिक स्थलों के दर्शन, साधना, भक्ति करने जाते समय अधिक सजधज अर्थात, श्रृंगारित होकर नहीं जाना चाहिये। यदि आपने श्रृंगार कर रखा है तो दर्शक, आगन्तुक, दर्शनार्थी, संत महात्माओं की भक्ति करने की बजाय आपके रूप सौन्दर्य एवं श्रृंगार को देखकर भक्ति मार्ग से भटक जायेगा। इसलिये धार्मिक स्थलों पर महिलाओं, जवान किशोरबालिकाओं को श्रृंगार रहित होकर देव दर्शन, संत महातमा की भक्ति करने जाना चाहिये।

धार्मिक स्थलों पर छेड़छाड़ लूटपाट की घटनाऐं घटित होने के समाचार अक्सर सुनने पढ़ने में आते हैं। इसमें छेड़छाड़ करने वालों, लूटखसोट करने वालों से अधिक दोष महिलाओं के अंग प्रदर्शन, श्रृंगार में गहने का पहनावा मुख्य कारण रहा है। यह उज्जवल भारतीय धार्मिक संस्कृति के लिए कलंक की बात है। हमारी धार्मिक संस्कृति को आदर्श, पवित्र एवं काम वासनाओं से मुक्त रखना है तो महिलाओं, किशोर एवं जवान बालिकाओं को ध ार्मिक स्थलों पर जाने पर वस्त्र पहनने का संयम और अधिक सुन्दर दिखने के मोह में आभूषणों से श्रृंगार का परित्याग करना चाहिये। ऐसा करने से धार्मिक स्थलों की धार्मिक मर्यादा को एवं संत महात्मा के त्यागमय जीवन को कभी आँच नहीं आयेगी। इसके लिये परिजनों को पहल करनी होगी और धर्म गुरूओं को भी सटीक समझाईश के उपदेश देने चाहिये।

आनुवंशिक संसाधनो के सतत उपयोग के लिए प्रोड्यूसर कम्पनी बेहतर विकल्प

Mk&çrki flg iokj

राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, करनाल निर्माता कंपनी एक कानूनी ढांचा है, जो सहकारी समिति और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जटिलताओं की कमियों को कम करता है। यह कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्माता कंपनी के रूप में पंजीकृत एक कॉर्पोरेट निकाय है, जो ऐसे किसानों या कारीगरों के रूप में प्राथमिक निर्माताओं द्वारा बनाई जाती है, जो फ्रोजेन सीमन, डेयरी व कृषि उत्पादन, कटाई, प्रसंस्करण, खरीद, ग्रेडिंग, पूलिंग (Pooling) करने में स्वयं शामिल होते है और सदस्यों की प्राथमिक उत्पाद के विपणन, बिक्री, माल और सेवाओं के निर्यात , आयात और इन गतिविधियों के लिए प्रासंगिक अन्य कार्यों से जुड़ा हुआ किसान है । इसका मुख्य उद्देश्य उन के बीच तालमेल बनाकर और प्राथमिक उत्पादन संभव मूल्य संवर्धन करके प्राथमिक उत्पादकों की आय में वृद्धि करना है (पँवार व सन्धू, 2014)। संक्षेप में, यह उत्पादन से खपत की श्रृंखला में बिचौलियों को हटाने के साथ ही प्राथमिक उत्पादकों व उपभोक्ताओं को अधिकार देता है। बिचौलियों का हिस्सा तालिका में निम्नप्रकार के अनुपात में रहता है।

fd lkuk d ifjJfedh e vlekurk

	टमाटर	आलू	गोभी	फूलगोभी	केला
अंतिम उपभोक्ता द्वारा कीमत का भुगतान (रू. प्रति किलो)	8.20	12.00	9.00	9.50	12.00
किसान द्वारा प्राप्त मूल्य (रू. प्रति किलो)	2.00	6.60	5.00	5.50	4.00
अंतिम उपभोक्ता द्वारा अदा मूल्य का किसान को प्राप्त प्रतिशत कीमत	24	55	65	58	33
प्रतिशत में (किसानों को प्राप्त कीमत से ऊपर अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान की कीमत)	310	82	80	73	200

lkr% प्रोफेसर एस. रघुनाथ एव डी. अशोक आई.आई.एम. बैंगलोर, द्वारा किया गया फील्ड में अध्ययन पर आधारित ।

इस तालिका में टमाटर क्रय के लिये अंतिम उपभोक्ता द्वारा अदा किये गए कुल मूल्य का मात्र 24 प्रतिशत ही उत्पादक किसान को तथा 76 प्रतिशत बिचोलियों को स्पष्ट प्राप्त हो रहा है ।

gfj;k.kk e Mjh QMj'ku }kjk n/k dh [kjhn] vkl r eY; rFkk dek;k x;k ufoy ykHk

Ø-l	fooj.k	2006&07	2007&08	2008&9	2009&10	2010&11
1	दूध की खरीद (000' किलोग्राम / दिन)	460	514	540	522	532
2	कार्यशील समितियों की (संख्या औसत)	5028	5979	6167	5194	4160
3.	उत्पादक को प्रति कि.ग्रा. दूध का अदा किया गया औसत मूल्य रू.	14.5	16.44	17.64	19.79	25.01
4.	नविल लाभ (लाभ रूपयों में)	203	359.58	465	188	807

ग्राम स्तर की समितियां दूग्धोत्पादकों से दुग्ध एकत्र करके दूध संघों को बेचती है। पहले दूध संघ फेडरेशन द्वारा चलाए जाने वाले संयंत्रों को दूध बेचते थे। वर्ष 1992 से फेडरेशन ने दूध संघो से पट्टे पर संयत्र ले लिए है, अतः अब दूध संघ दूध को प्रसंस्त करती है तथा फेडरेशन से पट्टे पर लिए गए दूध संयंत्रों में उस दूध को उत्पादों में परवर्तित करती है तथा बाजार में बेचती है। गौरतलब है कि इस प्रक्रिया में 4 प्रतिशत से कम वसा का दूध हरियाणा में क्रय ही नही हो पाता है और शंकर नस्ल की गाय के दूध में वसा 3.4 ही रहती है।

उपरोक्त पैटर्न के अनुरूप डेयरी उत्पादों में भी बिचौलियों का हिस्सा रहना स्वभाविक है। यह बिचौलिया हिस्सा राशि अगर डेयरी किसान को ही प्राप्त होने लगे तो शायद देशी पशुओं की उत्तम नस्लों का संरक्षण व सुधार गतिशील हो सकता है1 किसान

उत्पादक कम्पनी की जानकारी बारे विस्तार अध्ययन की आवश्यकता है। सामूहिक कारोबार करके ही किसान अपना जीवन बेहतर बना सकते है। प्राथमिक उत्पादक किसान ही उत्पादक कम्पनी का सदस्य अथवा मालिक बन सकता है। वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादन आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) कहा जाता है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अक्सर जीने का एक देश के मानक का सूचक माना जाता है। वर्ष 2014 के आकड़ों के अनुरूप सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 16 प्रतिशत व निर्यात आमदनी में 10 प्रतिशत योगदान है। जबकि जुलाई से सितंबर 2013 के दौरान ओधोगिक विकास दर 4. 8 प्रतिशत ही रही। वित्त वर्ष 2013–14 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 4.7 प्रतिशत रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है। लेकिन अपने सकल घरेलू उत्पाद के शेयर में गिरावट (2012–13 में 13.7 प्रतिशत) के साथ योगदान है। वर्ष 2009–10 के दौरान सेंट्रल सांख्यिकी कार्यालय के अनुमानों के मुताबिक पशुधन से उत्पादन का मूल्य 3, 40,473 करोड़ रूपये है। जो कृषि और एलाइड सेक्टर के कुल उत्पादन मूल्य का 24.73 प्रतिशत है।

भारतीय कृषि चौराहे पर है। शायद ही कोई प्रगति 60 प्रतिशत वर्षा आधारित खेती के तहत हो और हरित क्रांति के क्षेत्रों में वृद्धि रुकी हुई है। एक अरब से अधिक की आबादी की खाद्य और पोषक सुरक्षा एक मुश्किल स्थिति में है। उत्पादक कंपनियों के तंत्र का प्रयोग करके विभिन्न कृषि व डेयरी उत्पादों के मूल्य में संवर्धन कर जीडीपी व निर्यात आमदनी में अधिक योगदान देकर स्वयं का जीवन भी बेहतर किया जा सकता है। विशेष रूप से छोटे किसानों को एकीकृत करने के लिए उत्पादक कम्पनी बनाना ही रास्ता है। उत्पादक कम्पनी के मूल्य संवर्दित उत्पाद मूल्य श्रृंखला के साथ अंत में शुद्ध लाभ कृषि में रुचि रहने के लिए किसानों के लिए काफी लाभकारी होगा। उत्पादक कम्पनी की आम सभा द्वारा चयनित/निर्वाचित निदेशक मंडल के निर्देशन में, पेशेवरों द्वारा प्रबंधित व सदस्यों द्वारा इक्विटी योगदान के साथ एक विशिष्ट अवधि के लिए चलाने का प्रावधान है। उत्पादक कम्पनी बनाने के प्रयास किसानों/डेयरी उत्पादकों के लिए सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति हासिल करना है। इसका का मूल उद्देश्य सामूहिक विपणन के अतिरिक्त दुग्ध, बीज, खाद, ऋण, बीमा, ज्ञान, प्रसंस्करण, बाजार का नेतृत्व और विस्तार सेवाओं में अग्रणीय रहना है।

1) भारतीय कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत यह एक निगमित निकाय है। ऐसी कंपनियों की सदस्यता और स्वामित्व केवल "प्राथमिक उत्पादकों" या "निर्माता संस्था" के पास ही रहेगी और सदस्य इक्विटी का कारोबार नहीं किया जा सकता। लेकिन, यह केवल उत्पादकों कंपनियों के निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्थानांतरित किया जा सकता है।
2) निर्माता कंपनी अधिनियम में निर्दिष्ट खंड (581& A से 581&ZT) को छोड़कर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खंड निर्माता कंपनियों पर लागू होंगे। यह एक सामान्य निजी या कंपनी लिमिटेड से अलग है (विवरण के लिए निर्माता कंपनी अधिनियम का उल्लेख देखे)।
3) निर्माता कंपनी का सीमित दायित्व है और केवल शेयर पूंजी तक सीमित है। सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा प्राप्त शेयरों की अवैतनिक राशि तक सीमित है।
4) न्यूनतम चुकता अधिकृत पूंजी एक निर्माता कंपनी के लिए 5 लाख रुपए है। अर्थात मिलान इक्विटी अनुदान प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किसान निर्माता कम्पनी के पास 5 लाख रुपये होने चाहिए।
5) एक निर्माता कम्पनी बनाने के लिए आवश्यक उत्पादकों की न्यूनतम संख्या 10 है। सदस्यों की अधिकतम संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है। और यह संख्या व्यवहार्यता और जरूरत के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। कृषि व डेयरी उत्पाद आधारित निर्माता कम्पनी में 800–1000 उत्पादक प्रारंभिक वर्षों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और कम्पनी में वृद्धि के अनुरूप उत्पादको की संख्या 2000 तक बढ़ाई जा सकती है।
6) निर्माता कंपनियों में किसी भी सरकारी या निजी इक्विटी की हिस्सेदारी नहीं हो सकती। इसलिए उत्पादक कम्पनी सार्वजनिक या पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बन सकती।
7) एक निर्माता कम्पनी का ऑपरेशन क्षेत्र सम्पूर्ण देश है।

lgdkjh lkslk;Vh o fuekrk dEiuh e fHkUurk d ekin.M

Øe l	ekin.M	lgdkjh lkslk;Vh	fuekrk dEiuh
1.	पंजीकरण	सहकारी सोसायटी अधिनियम	भारतीय कम्पनी अधिनियम
2.	उद्देशय	एकल ऑबजेक्ट	मल्टी ऑबजेक्ट
3.	आपरेशन के क्षेत्र	प्रतिबंधित विवेकाधीन	भारत की पूरी संघ
4.	शेयर	गैर व्यापार योग्य	व्यापार योग्य नही लेकिन हस्तांतरणीय सम मूल्य पर सदस्यों तक सीमित

5.	सदस्यता	कोई व्यक्ति और सहकारी समितियां	कोई भी व्ययक्ति, समूह, एसोसिऐशन, गौशालायें, ब्रिड सोसायटी, निर्माता का सामान या सेवायें
6.	लाभ – सहभाजन	शेयरों पर सीमित लाभांश	व्यापार की मात्रा के अनुरूप
7.	मताधिकार	एक सदस्य, एक वोट है, लेकिन सरकार और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को वीटो शक्ति का अधिकार	एक सदस्य, एक वोट. सदस्यों का कंपनी के साथ लेनदेन नहीं होने पर वोट नहीं कर सकते
8.	सरकारी नियंत्रण	अत्यधिक हस्तक्षेप की हद तक संरक्षण	कम से कम, सांविधिक आवश्यकताओं को सीमित करने के लिए
9.	स्वायत्तता की हद	"वास्तविक दुनिया परिदृश्य" में सीमित	पूरी तरह से स्वायत्त, अधिनियम के प्रावधानों के भीतर आत्म फैसला लेना
10.	भंडार	यहाँ लाभ हैं, तो बनाया जाता है	हर साल बनाने के लिए अनिवार्य
11.	उधार क्षमता	प्रतिबंधित	अधिक स्वतंत्रता और विकल्प
12.	अन्य कॉर्पोरेट / व्यावसायिक घरानों / गैर सरकारी संगठनों के साथ संबंध	लेन – देन आधारित	प्रोड्यूसर्स और निगम इकाई एक साथ एक निर्माता कंपनी फ्लोट कर सकते हैं

उत्पादक कम्पनी की खास बात यह भी है कि सरकार की तरफ से दस लाख तक की इक्विटी अनुदान निधि भी मिलती है। इसके अतिरिक्त निर्माता कंपनी का सीमित दायित्व है और केवल शेयर पूंजी तक सीमित है। दिवालिया अथवा बीच में ही बंद होने पर सदस्यो की व्यक्तिगत संम्पति प्रभावित नही होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त भूमि की जोत लगातार कम होने पर डेयरी उत्पाद व गाय, भेड़, बकरी, ऊँट ,घोड़े, मुर्गिया तथा भैंस आदि के उत्तम सांडों के वीर्य और प्रा.तिक प्रजनन क्षेत्र में भी सामूहिक कारोबार आरंभ करके लाभ पाने के अतिरिक्त देशी पशुओं की नस्लों को संरक्षित रख कर अगली पीढ़ी को सौंपा जा सकता है। इस विषय पर विभिन्न सेमिनार शीघ्र आयोजित करने का प्रस्ताव भी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि, यह निर्माता कंपनी प्राथमिक उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए एक लाभकारी मार्ग है1 इसलिए, किसानों और कारीगर निर्माता कंपनियों के गठन में पहल करने के लिए लघु व माध्यम वर्ग के डेयरी व मीट उत्पादक को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

घाटे में क्यों किसान?

Ñ".k ykd fe=

प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मेादी को उदार अर्थिक नीतियों का समर्थक माना जाता हैं। जिस तरह से वो उद्योगपतियों के चहेते हैं, उससे भी यह बात साबित हेाती है और विश्व अर्थव्यवस्था में जिस तरह से उनके हर कदम की पदचाप सुनाई पड़ती है, वह भी इस बात की तस्दीक करती है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री किसानों के संबध में भी कोई आधुनिक, उदारवादी और तार्किक रवैया अपनाएगें? यह अटपटा–सा लगने वाला सवाल इसलिए, क्योंकि शायद ही देश में आज खेती के अलावा दूसरा कोई ऐसा पेशा हो जिसमें आमतौर पर आय लागत से या तो कम होती है या फिर सिर्फ इतनी होती है कि किसी तरह से लागत निकल आए। ये हैरान करने वाली बात लग सकती है मगर सच्चाई यह कि 90 फीसदी से ज्यादा किसान अगर श्रम और खेती पर किए जाने वाले अपने निवेश यानी लागत जोड़ लें तो उन्हें खेती से जो मिलता है, वह उससे कम होता है। फिर कुछ लोग कहेंगें कि अगर खेती घाटे का सौदा है तो यह किसानों के द्वारा क्यों की जा रही है? ;g bruk ekdedd loky g fd bldk ,d gh tokc g ykpkjhA क्योंकि अव्वल तो जो लोग खेती में लगे हुए हैं, उनमें से 99 फीसदी लोगों के पास खेती के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। साथ ही यह भी ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात है कि gekj ;gk [krh okdb jkt xkj ugh] thoup;k gA धरती को हिन्दुस्तानी लोग सिर्फ मां कहते ही नहीं है बल्कि उसे मां का मान भी देते हैं। blfy; T;knkrj fdlku [krh dk vkthfodk l T;knk xgLFk /ke dk miØe ekurs gA

शायद यही किसानों की सबसे बड़ी ताकत है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। अगर किसानों के पास खेती करना छोड़ देने का विकल्प होता तो शायद आज वह स्थिति न होती जो है। देश में खेती के अलावा उत्पादन का ऐसा कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है, जहां उत्पादन का मूल्य उत्पादक न तय करके सरकार तय करती हो। केवल खेती के साथ ही ऐसा हो रहा कि खेती किसान करता है, मगर कृषि उत्पादकों की किमतें सरकार तय करती है। बाजार भी नहीं। यही किसानों की सबसे बड़ी विडंबना और उनके शोषण का सबसे बड़ा जरिया है। एक तरफ इन दिनों जहां पूरे देश में मंहगाई का रोना रोया जा रहा है। जब बाजार में पिसा आटा, पैंकिग होकर 35—40 रूपये किलो बिक रहा है ठीक उसी समय किसानों के गेंहू की किमत अभी भी 1400—1450 रूपये प्रति क्विंटल के इर्दगिर्द ही घूम रही है। जबकि तमाम अध्ययन और तमाम आयोग कह चुके हैं कि किसानों की लागत के मुकाबले उनकी आय शून्य से भी नीचे, नकारात्मक हो रही है। LokehukFku vk;kx d erkfcd gky d lkyk e [krh dh ykxr e tk c<kÙkjh gbl leFkd eY; mld edkcy çfr fDoVy 150&200 :i; de gA exj dku lu\

दरअसल कृषि और किसानों के साथ आजादी के साथ ही भेदभाव शुरू हो गए थे। आजादी के बाद सरकार ने एक कृषि मूल्य आयोग बनाया जिसका काम फसल का मूल्य तय करना तय किया गया, लेकिन ऐसा ही कोई आयोग उद्योंगों को अपने उत्पादन की किमत तय करने की छूट दी गई। जबकि किसानों को यह छूट नहीं दी गई। किसानों को हर चीज तो बाजार से खरीदनी पड़ती है, वह भी बाजार की कीमतों पर, लेकिन जब उन्हें अपनी फसल बेचने को मौका मिलता है तो उनकी फसल की कीमत सरकार तय करती है। ;g ykdr= g ;k vèkjxnh\ मजे की बात यह है कि देश में चौधरी चरण सिंह जैसे किसान नेता प्रधानमंत्री बने भले छह महीनों के लिए ही। देवीलाल, चन्द्रशेखर और देवगौड़ा को भी सीधे—सीधे खेती से रिश्ता रहा है। इस सबके बावजूद इन सबने खेती के लिए कुछ नहीं किया। कुछ न करते महज यह सुनिश्चित कर देते कि जैसे कारखाने का मालिक अपने कारखाने में बनी चीजों की कीमत खुद तय करता है, एक प्रकाशक अपनी किताब की कीमत खुद तय करता है, एक कलाकर अपनी कला की कीमत खुद तय करता है, उसी तरह किसान को भी यह हक देते कि वह अपनी फसल की कीमत खुद तय करे तो कुछ बात ही और होती।

आजादी के बाद उम्मीद थी कि सरकार किसानों के साथ न्याय करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृषि समर्थक मूल्य आयोग ने कृषि उत्पादों के मूल्यों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में लगातार फासला बढ़ता गया। यही फासला दोनों की आय में भी बढ़ता रहा। औद्योगिक उत्पादों की तुलना में फसल का मूल्य कम होता चला गया। इस तरह किसान की हैसियत लगातार घटती गयी। ये सबसे बड़ा अन्याय है जो आजादी के बाद किसानों के साथ हुआ। उद्योग की हकदारी बढ़ाने से उघोग जगत मालामाल होता गया, लेकिन कृषि मजबूरी और लाचारी का सबब बनती गई। जिस खेती के बारे में एक जमाने में कहा गया था, mÙke [krh] ef)e cku- --- वह खेती आज लाचारी का सौदा बन गया है। आज कोई भी खेती करना नहीं चाहता, क्योंकि गांवों में कहावत है tk cu fdlku] gk filkuA

यह भी विरोधाभास की पराकाष्ठा है कि बाकि सभी मामलों में भले सरकार बाजरावादी नजरिया अपनाए, लेकिन कृषि मूल्यों के मामले में वह बिल्कुल समाजवादी नजरिया रखती है। नतीजा सबके सामने है। देश को सबसे बड़ी आबादी की, देश की ताकत और खुशहाली में यह हिस्सेदारी नहीं है जो उसके आकार के हिसाब से होनी चाहिये। आज जीडीपी में उद्योग 70 फीसदी तक का योगदान करते है। वो भारत की संपदा निर्माण में सबसे ज्यादा दखल रखते हैं। जबकि खेती का हिस्सा घटते—घटते 14 फीसदी तक पंहुच गया है। यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि जीडीपी में खेती अब कोई मायने नहीं रखती।

अगर आजादी के बाद सरकार को कृषि उत्पादों की कीमत तय ही करनी थी तो उसे करना यह चाहिये था कि 1950 में फसल के मूल्य का अनुपात लगातार बनाये रखना था। इससे किसान के रम को उचित कीमत मिलती और साथ ही किसानों की माली हालत तो बेहतर होती ही, किसान के लड़कों को शहरों में आकर अपने पुश्तैनी पेशे के बारे में बताते हुए शर्म नहीं आती या उनके पेशे को सुनकर गैर कृषि पेशे वाली पृष्ठभूमि से आए उनके साथी स्वतः यह न मान लेते कि यह तो बेचारा गांव का गरीब है। इससे और भी कई फायदे होते खेती न सिर्फ नए—नए प्रयोगों की भी उत्सुकता और उत्साह बनी रहती। इसके अलावा खेती के बेहतर रहते देहात से शहरों की और बेतहाशा पलायन नहीं होता जो कि आज की कड़वी हकीकत है।

ईर्ष्या अग्नि है, परन्तु अग्नि का गुण उसमें नहीं है, वह ह्रदय को फैलाने के बदले और भी संकीर्ण कर देती है।

किसान वर्ग संकट में – कम करनी होगी कृषि पर निर्भरता

Ikeiky 'kkL=h

यह बात लबें समय से उठ रही है कि हमारे देश में अब कृषि की औसत जोत इतनी कम हो गई कि इससे भरण–पोषण नहीं हो सकता। कृषि में उत्पादकता बहुत कम होते जाने के कारण यह बात उठती रही है कि अब कृषि पर निर्भर आबादी को कम किए जाने की भी जरूरत है। ताजा 70वें राष्ट्रीय सर्वेक्षण से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। यह समस्या लगातार गहराती जा रही है। मुझे याद है कुछ समय पहले तक 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों की संख्यां 83 प्रतिशत हुआ करती थी। अगर यही स्थिति रही तो हालात बद से बदतर होते जांएगे। इस स्थिति से निकलने के लिए सरकार को दो आयामी रणनीति पर अमल करना चाहिये। पहली कृषि निर्भर आबादी का अनुपात कम करना, दूसरा उत्पादन बढ़ाना।

कृषि निर्भर आबादी का अनुपात कम करने के लिए सबसे जरूरी बात यह होगी कि वर्तमान में कृषि पर निर्भर लोगों को वैकल्पिक और पूरक रोजगार उपलब्ध कराये जाएं। यह तभी संभव है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धन्धे स्थापित हों। यह बात बिल्कुल गलत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धन्धें नहीं खुल सकते अथवा वहां इनकी जरूरत नहीं है। यह सब हो सकता है, लेकिन सरकार को सही रणनीति अपनाने की जरूरत है। सरकार को न तो खुद उद्योग लगाने हैं और जमीन अधिग्रहण करना है। सरकार बस वही काम करे जो उसके जिम्मे हैं। सरकार अगर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, शिक्षा, सुरक्षा, और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करा दे और लोगों पर पांबदी लगाने के बजाय उन्हें छूट दे दे तो इन क्षेत्रों में उद्योग स्वतः आ जायेगें। उद्योग लगाने वाला सरकार से बेहतर जानता है कि वह कहां–कौन सा उद्योग लगाए। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने में बाधा कुछ है तो उसका यही कारक है। खेती को दिन में पांच–छह घंटे बिजली मिले तब भी हो सकती है पर उद्योग धंधों को तो 24 घंटे बिजली चाहिये। इसके बिना वह लाभ का सौदा नही बन सकते। इसी तरह इन उद्योग धंधों में कुशल लोग काम करने के लिए तभी तैयार होगें जब उन्हें वहां पर परिजनों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधायें मिलें, बच्चों के लिए अच्छी प्राथमिक शिक्षा हो। साथ ही सुरक्षा का माहौल तो सबको चाहिये। अगर सरकार इतना काम कर दे तो ग्रामीण क्षेत्र का तो भला होगा ही शहरों का भी भला होगा। आज हमारे शहरो में एक तरफ तो आबादी का घनत्व पहले ही बहुत अधिक है दूसरा शहरों में जमीन से लेकर मजदूरी और कच्चा माल सब कुछ अधिक दामों पर मिलेगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धन्धें लगाने की दिशा में कदम बढ़ाने में ही सबका भला है। bl! {k=h; fodUnhdj.k Hkh dgk tk ldrk g] अर्थात देश के हर क्षेत्र, भाग को कमोबेश एक जैसी बुनियाद सुविधाएं मिलें।

इसी तरह सरकारें कृषि को ढ़ाल तो बहुत पीटती हैं पर उसकी बेहतरी के लिए जो उनके वश में है वो करती नहीं हैं। भारत में कुल 1440 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर खेती होती है। इसमें 60 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जो अब भी सिंचाई के लिए वर्षा पर आधारित है। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्र की अस्सी प्रतिशत गरीब आबादी इस क्षेत्र की औसत अनाज उत्पादकता वर्षा आधारित क्षेत्र में 3 से चार गुना तक अधिक है। उदाहरण के तौर पर अगर वर्षा आधारित क्षेत्र में प्रति हैक्टेयर 11 क्विंटल अनाज पैदा होता है तो सिंचाई संपन्न क्षेत्र में प्रति हैक्टेयर 40 क्विंटल तक अनाज पैदा होता है। इस तरह अगर समूची कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो 864 लाख हैक्टेयर वर्षा आधारित क्षेत्र की उत्पादकता बढ़कर चार गुना हो सकती है। इसलिए सरकार को कुछ करना है तो उसे सबसे पहले सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करना चाहिये। ऐसा करने से कृषि और उद्योग दोनों का भला होगा।

सरकार को तीसरा प्रयास यह करना है कि उसे अपनी विपगा और वितरण प्रणाली को सुधारना होगा। फल, सब्जी आदि में जो मंडी प्रणाली सरकारों ने लागू कर रखी है उससे किसी का भला नही होता, न उत्पादकों का और उपभोक्ताओं का। अभी हालात यह है कि इस मंडी और लाइसेंस प्रणाली के चलते जिस दाम पर किसान सब्जी आदि मंडी में बेचता है उससे कई गुना अधिक कीमत पर वह उपभोक्ता को मिलती है। चौथा प्रयास है नई तकनीक, शोधों और जानकारियों को किसानों तक पहुंचाना व उनके बारे में जरूरी प्रशिक्षण देना।

वैवाहिक विज्ञापन

- SM4 Divorced (No Issue) Jat Girl 30/5'7" B.A., LLB., L L M Doing Job. Rs. 40,000/- PM. Avoid Gotras: Panwar, Baliyan. Cont.: 09017293487
- SM4 Jat Girl 27/5'2" Ph.D Net Cleared. Employed as Assistant Lecturer in DAV University, Jallandhar. Avoid Gotras: Kaliraman, Malik. Cont.: 08699983183
- SM4 Jat Girl (DOB July, 1988) 27/5'3" Bsc.Computer Science, MBA Gold Medalist from PU Chandigarh. Net qualified. Working as Assistant Manager in Nationalized Bank at Panchkula. Own house at Panchkula. Match preferred from Panchkula, Chandigarh, Mohali (Trycity). Avoid Gotras: Sangwan, Dangi, Doon. Cont.: 09988346779.
- SM4 Jat Girl (DOB 13.09.1987) 27.6/5'5" M. Tech. Employed as Lecturer at Rohtak. Avoid Gotras: Nandal, Pawaria, Ahalawat. Cont.: 09996060345, 09811658557
- SM4 Jat Girl 26/5'3" MCA, MBA Employed as supervisor in Central Govt. on contract basis. Avoid Gotras: Bagri, Nehra, Nain. Cont.: 09417415367
- SM4 Jat Girl 23/5'2" B.Tech (CSE) Avoid Gotra: Malik, Hooda, Joon. Cont.: 09780336094
- SM4 Jat Girl, 26/5'2" M.Sc. (Microbiology) Working as Senior Lab Technician in AL Chemist Hospital Panchkula. Avoid Gotras: Mittan, Kharb, Dahiya, Kadyan. Cont.: 08146082832.
- SM4 Jat Boy 26.9/5'7" M.C.A. Employed as Project Engineer in Vipra Co. at Banglore. Avoid Gotras: Grewal, Antil, Dalal. Cont.: 09417629666
- SM4 Jat Boy 26/5'7" BDS Doctor Doing Job. Avoid Gotras: Narwal, Malik, Ghanghas. Cont.: 09417359925

चन्द्रमां अपना प्रकाश सारे आकाश में फैलाता है, परन्तु अपना अन्धेरा अपने भीतर ही रखता है। – रवीन्द्रनाथ ठाकुर

दुनिया भर में कृषि पर बढ़ता संकट

nfonj 'kek

[krh dh n'kk vefjdk vkj ;jksi e: Hkh [kjkc g] tgka bl Hkkjh lfClMh nh tkrh gSA Hkkjr dh rjg vefjdk e: Hkh ;g lkjh lfClMh Ñf"k vk/kkfjr cMs m|kxksa e: pyh tkrh gSA vefjdk e: NksVs fdlkuksa dks ?kj pykus ds fy, nk&rhu ukSdfj;ka rd djuh iM+ jgh gSA vf/kd tkudkjh ds fy, i<s ;g jkspd ys[kA

कुछ साल पहले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम गुलबर्गा में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने छात्रों से कड़ी मेहनत कर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और उद्यमी बनने का अह्वान किया। जब उन्होंने अपना भाषण खत्म किया तो एक युवा खड़ा हुआ और उसने कलाम से पूछा कि उन्होंने युवाओं से किसान बनने को क्यों नहीं कहा? यह सुनकर कलाम तो अवाक रह गए। उन्होंने लंबा–सा कोई जवाब दिया पर उस युवा ने उनकी दलील को खारिज कर दिया और खेती के खिलाफ जो पक्षपात हो रहा है, उसे सामने रखा।

इस घटना की याद मुझे तब आई जब मैं अमेरिका के एक किसान के मार्मिक निंबध को पढ़ रहा था। इस किसान ने नपूर्थाक टाइम्स में लिखा, 'खाद्य आंदोलन का भद्दा रहस्य यह है कि जिस छोटे किसान के बहुत गुण गाये जाते हैं, वह जीविका ही कमा नहीं पा रहा है। खेती के औजार रखने के बाद हम दूसरा और तीसरा जॉब करने जाते हैं ताकि खेती बची रहे।' अमेरिका में 91 फीसदी कृषि आधारित परिवारों को घर चलाने के लिए आय के एक से अधिक स्त्रोतों का सहारा लेना पड़ता है।

यह उस देश में हो रहा है, जहां खेती को अगले दस साल के लिए 962 अरब डॉलर की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। यूरोप में भी स्थिति इतना ही खतरनाक है। यूरोप के सालाना बजट का 40 फिसदी खेती को देने के बाद भी वहां हर मिनट में एक किसान खेती छोड़ देता है। नेशनल फार्मर्स यूनियन के सर्वे में पता चला कि 70 से ज्यादा कृषि आधारित व्यवसाय मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन इस खाद्य श्रृंखला में किसान ही हैं, जो घाटे में चल रहे हैं। जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि अमेरिका व यूरोप में 80 फीसदी से ज्यादा सब्सिडी खेती आधारित व्यवसाय में चली जाती है।

किसान एक मरती हुए प्रजाति बनता जा रहा है। न्यूजवीक में मार्क्स कुटनर कहते हैं, 'बरसों से अमेरिका में किसान, आम आबादी की तुलना में ज्यादा आत्मदाह कर रहे हैं। ठीक आंकड़ा हासिल करना कठिन है, क्योंकि ज्यादातर मौतें दर्ज ही नहीं होतीं।' एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में हर साल मौत को गले लगाने वाले 2,80,000 ग्रामीणों में 80 फीसदी भूमि अधिग्रहण के शिकार बने लोग होते हैं। भारत में 1995 के बाद से लगभग 3 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं। भारत में भी अमेरिका की तरह ये मामले पूरी तरह दर्ज नहीं होते।

कोई महामारी या कोई ऐसी आपत्ति नहीं आई है कि भारत सहित दुनियाभर में किसान बेमौत मारे जा रहे हैं यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का नया रूप है, जिसमें किसान को हाशिये पर ध ाकेला जा रहा है। इसके साथ खेती में अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त, पर्यावरण को विनाश पहचानने वाली कंपनियों को लाया जा रहा है। आमतौर पर यह माना जा रहा है कि किसी भी राष्ट्र को अर्थिक रूप में सक्षम बनाना है तो खेती के योगदान को धीरे–धीरे हाशिये पर डालना होगा। मुझे लगता है कि 2020 तक भारत में खेती का जेडीपी में योगदान 10 फीसदी तक ला दिया जाएगा। हमारे यहां खेती की यह हालत है कि 2007 से 2012 के बीच 3.2 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ दी है।

ये कर्जे वाले

jkgh] t;iqj

अपने प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े मार्के की बात कही–गरीब अपना पूरा कर्जा चुकाता है जबकि अमीर करोडों का कर्जा खा जाता है। दरअसल इसका कारण है–हाजमा। ईमानदारी नामक बीमारी के कारण गरीब का हाजमा प्रायः खराब रहता है। वह कर्जा पचा नहीं सकता। कर्जा लेते ही उसके ^fny* में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। वह बीमारी उसे तब तक लगी रहती ह जब तक वह उसे चुका नही देता। अमीर इस तरह की बेवकूफाना बीमारियों से मुक्त रहता है। वह सरकारी गैर सरकारी, जान–पहचान वालों का, अनजान लोगों का यानी किसी का भी कर्जा सहजता से पचा लेता है। कई तो ऐसे हरफनमौला है जो अपने सालों और सगे भाईयों तक से लिया कर्जा डकार जाते है। अब सुन रहे हैं कि एक मंत्रीजी के महा कर्जापाचक पुत्र ने अपने आकार से साढ़े तीन गुना कर्जा ले लिया। मजे की बात देखिए कि हमारे जैसे लोग जो कर्जा खाने में माहिर होते है उनके सामने अच्छे–अच्छे लोग हाथ में कर्जा लिए ऐसे खड़े रहते है जैसे बारात प्रवेश के समय मोगरे की माला लिए घराती खडे रहते हैं। जो बाराती माला डलवाना भी नहीं चाहता उसके गले में जबरदस्ती माला ठोस कर ही दम लेते है।

दरअसल कर्जा पचाना एक कला है लेकिन इससे भी बड़ी कला है दबाना। देश के बैंकों ने कितने हजार करोड़ का कर्जा बांट रखा है। ये आंकड़े हम इसलिए नहीं लिख रहे कि उस रकम को याद करते ही हमारी धुक–धुकी बुलेट ट्रेन की माफिक रफ्तार पकड़ लेती है। मजे की बात यह है कि इसमें से नब्बे प्रतिशत कर्जा अमीरों के पास है और वे कर्जा चुकाने का नाम नहीं ले रहे।

हम तो मोदी जी से गुजारिश करते हैं–भाई। बुलेट ट्रेन बाद में चलवाना, जनता पखाने ठहर के बनवाना, सबसे पहले देश के अमीरों ने जो कर्जा दबा रखा है उसे वसूल लो। काले धन के बारे में तो सिर्फ अनुमान है लेकिन यह कर्ज तो जगजाहिर है। हम यह भी दावा कर दें कि चाहे सिंह सरकार हो या मोदी दरबार, अमीरों से कर्ज उगाहने में किसी को भी ज्यादां दिलचस्पी नहीं है। एक तरफ हम हैं जिस दिन कर्ज को पी लेते हैं उस दिन चढ़ती ही नहीं। इससे इतना डरते हैं मानों यह ^d t.* न हुआ भूत हो गया।

चन्द्रमां अपना प्रकाश सारे आकाश में फैलाता है, परन्तु अपना अन्धेरा अपने भीतर ही रखता है। – रवीन्द्रनाथ ठाकुर

जाट समाज में प्रमुख गौत्र

& jkds'k lijkgk

Hkkjr ds tkV lekt esa cgqr lh fo'ks"krk,¡ gSa tks bl lekt dks J"B rFkk vkn'kZ cukrh gSaA bu fo'ks"krkvksa esa ls tkV lekt dh ,d cgqr gh egRoiw.kZ rFkk vkn'kZ fo'ks"krk blds xks= 0;oLFkk gS çkphu dky esa xks= 0;oLFkk ds LFkku ij o'k 0;oLFkk dk vf/kd çpyu Fkk rFkk o'k esa dbZ çHkko'kkyh rFkk egRoiw.kZ 0;fDr;ksa ds uke ij xks= o;oLFkk 'kq: gbZ blfy;s dgk x;k gS fd ,d o'k ls dbZ xks= çpyu esa vk;s gSa vFkkZr lo±çFke _f"k;ksa] nsoksa rFkk çkÑfr ds uke ls o'kks dh LFkkiuk gbZ mlds i'pkr ,d o'k ls dbZ xks= cus rFkk ,d xks= ls mixks= cus x;s rFkk orZeku le; esa mixks= Hkh LorU= :i ls vyx xks= ds uke ls çpyu esa gS bl le; tkVksa esa xks= ds vk/kkj ij gh fookg 0;oLFkk LFkkfir gS rFkk fookg ds le; yMds rFkk yMdh ds ekrk firk rFkk nknh ds xks= ds lHkh lnL;ksa dks ,d ifjokj dh rjg ekurs gS blfy;s tkV lekt esa lexks= fookg dk lekftd ekU;rk çkIr ugha gSA orZeku le; esa if'peh lH;rk ds çHkko esa vk/kfud lksp ds vk/kkj ij tks ykx lexks= fookg dk leFkZu djrs gS ckn esa mUgs lexks= fookg ds nq"ifj.kkeks ds dkj.k i'pkrki djuk iMrk gSA blfy;s tkV lekt dh xks= 0;oLFkk vfr mÙke gS bl le; tkV lekt esa xks= rFkk mixks= dh l[;k djhc nl gtkj gS rFkk mues ls dqN çeq[k tkV xks=ksa esa tkV lekt ds cgqr gh egRoiw.kZ 0;fDr gq, gS ftUgksus fofHkUu {ks=ksa esa dke djds ns'k o lekt dk xkjo c<k;k gS ftudk lf{kIr fooj.k bl çdkj gS %&

Ø-l-	xks= dk uke	çfl) 0;fDr
1-	vgykor] ,ykor	dSIVu nyhi flag vgykor tkV bfrgkldkj
2-	v=h] v=s	Jh pj.kthr flag v=h çkQslj] ngyh
3-	vrqy] vury] vfrqy	lhek vfrqy ,FkfyV Hkkjr
4-	vk[ky] vkyk	Loå Jh lhljke vkyk ¼jktLFkku½ dsUnzh; ea=h
5-	dkyhjeu] dkyhjke.kk	ekLVj pUnxh jke igyoku fgUn dslj
6-	dMokl jk	Mk- ,l-ih-,l- dMoklj k iwoZ oKkfud] HAU fglkj
7-	dqM] dq.M	çkå Nrjiky flag dqM] iwoZ ea=h gfj;k.kk
8-	dfn;ku] dkn;ku	çkå 'kj flag Hkwriwo mie[;ea=h iatkc
9-	dkyqj] dyqj	Mk- gjhjke dyqj] ,l-d- vLirky fldj ¼jkt-½
10-	dklfu;k	Jh jkeçrki dklfu;k Hkwriwo fo/kk;d jktLFkku
11-	[kk[kj] [kkdj	lkfu;k [kk[kj dykdkj vfHkusrh
12-	[khpM	Jh vtqu flag pkS/kjh ¼[khpM½
13-	x<oky	Mk- lgnso flag x<oky] Ñf"k oKkfud jktLFkku
14-	xksnkjk	pkS- lkgc jke xksnkjk] lektlsoh o iwoZ lkaln jktLFkku
15-	fxy] 'kj fxy	Jh ,e-,l- fxy iwoZ e[; pquko vk;qDr] Hkkjr
16-	xgykr] xgykor	esatj vuq xgykr] Hkkjrh; lsuk ls egkohj pØ çkIr
17-	/kkIfy;k	Jh x.ks'k ukjk;.k /kkIfy;k] lkekftd dk;ZdrkZ
18-	pkgj	pkS- vt; flag pkgj] v/;{k vf[ky Hkkjfr; tkV egklHkk
19-	lkydh	pkS- Qy flag lkydh] LorU=rk lsukuh
20-	pVBk	lå gjekfgUnz flag pVBk] foÙk ea=h gfj;k.kk ljdkj
21-	pgy	Mk-,l-,e- pgy] Mhu ,p-,-;w- gfljk
22-	fNdkjk] fpdkjk	Mk- Mh-oh- fpdkjk] çkQslj fnYyh fo'ofo|ky;] fnYyh
23-	tk[kM	Mk- cyjke tk[kM] Hkwriwo fo/kk;d ujkyk
24-	tkxyku	Jh jkel:i tkxyku] LorU= lsukuh
25-	tVjk.kk	Jh tlorU jk.kk Hkwriwo fo/kk;d ujsyk
26-	>k>fM;k	Jh uUnyky çFke fcxsfM;j pw: jktLFkku
27-	fVokuk	Jh xq:pj.k flag Vkgjk] iwoZ v/;{k xq:}kjk çcU/kd desVh
28-	r{kd	Jh cyoar r{kd] fgUnh i=dkj] p.Mhx<
29-	Bkdjku	Jh fojsUnz flag Bkdjku] xksyM eMfyLV igyoku

दुनिया में दो ही ताकतें हैं, तलवार सदैव कलम से पराजित होती है। – अज्ञात

30-	Buok] Buvk	Jh jktk egUn çrki
31-	Mkxj	pk- vkUn flg Mkxj] fo/kk;d gfj;k.kk
32-	Mkxh] nkxh	Pkk- Qrg flg Mkxh] vkb-,-,l- gfj;k.kk
33-	MMh	Jh jke'oj yky MMh] Hkrio lkln chdkuj
34-	Mckl	pk- ij.k flg Mokl fjVk;M çkQlj fnYyh
35-	<kdk	Jh x.kir flg <kdk dkjfxy ;) d uk;d
36-	f<Yyk	lå çdk'k flg ckny e[;e=h itkc
37-	<y	pk- ny flg Hkrio flpkb o fctyh e=h gfj;k.kk
38-	<kMk	Jh uj flg <kMk Hkrio e=h gfj;k.kk
39-	rofr;k	pk- pj.k flg Hkrio ç/kkue=h Hkkjr
40-	rkej	Jh jktk thou flg rkej 'kkld fnYyh
41-	Fkkjh	Jh lkukjke tkV lkekftd dk;drk okMej jktLFkku
42-	nyky	Mk- gjLo:i flg] Hkrio jkT;iky ikMpjh
43-	nloky	Jh jktchj flg nloky] ofj"B ifyl vf/kdkjh Mh-vkb-th- gfj;k.kk
44-	nfg;k	etj gkf'k;kj] ijeohj pØ l ijLÑr Hkkjrh; luk
45-	n;ky	Jh /keUn] e'kgj fQYe vfHkurk
46-	/ku[kM] /kudM	Jh txnhi /kudM] jktfufrK jktLFkku
47-	/kkY;k	Jh ohj rtkth ykdnork] jktLFkku
48-	uu] u.k	Jh gjh'k pUn uu LorU=rk lukuh jktLFkku
49-	ujoky	Jh çrki flg ujoky io etj tujy Hkkjrh; luk
50-	fuBkjnky	ykB fuBkjoky] LorU=rk lukuh
51-	ugjk	Jh txnh'k ugjk] Hkrio flpkb e=h gfj;k.kk
52-	ukgokj	pk- prhjke oek çfl) m/kkxifr Qjhnkckn
53-	iokj] iokj	pk- gjiky flg iokj Hkrio lkln
54-	i?kky	pk- txchj flg i?kky Hkrio lkln fHkokuh
55-	ipgjk] ipgj	Pkk- jktUniky flg] lokfuor ftyk ,o l= U;k;/kh'k t;ij
56-	ifu;k	Jh t; ukjk;.k ifu;k] io dfcuV e=h jktLFkku
57-	fiykfu;k	Jh Kku çdk'k fiykfu;k] lokfuor Mh-th-ih- jktLFkku
58-	Qkxkv] QxfM;k	lcnkj pukjke QxfM;k çFke egkohj pØ fotrk
59-	cMkfu;k	Jh ujUn cMkfu;k io lkln] p: jktLFkku
60-	cnk	Jh jkepUn cnk io lkln Qjhnkckn
61-	ckuk	Jh fnyhi pkjh ckuk io fo/kk;d trkju ¼ikyh½
62-	cjk] cj	fuelyk cjk igyoku flyoj eMy fotrk dkeu oYFk xe
63-	cYgkjk	Jh egUn pk/kjh] io ç/kkue=h fQth
64-	fclyk	pk- jktUn flg fclyk io fo/kk;d cYyHkx< ¼gfj;k.kk½
65-	Hkk[kj] Hkkdj	Jh fnyl[k jk; pk/kjh io fo/kk;d yNeux< jktLFkku
66-	HkVVy	Jhefr jkftUn dkj HkVVy io e[;e=h itkc
67-	Hkkn	pkñ euQy flg Hkkn lkln lnL; chdkuj
68-	eM e.M	Jh nkyr jke eM ç/kku fdlku ekpk guekux< ¼jkt-½
69-	egyk	dkejM f=ykd flg] Hkrio fo/kk;d ftyk lhdj ¼jkt-½
70-	ekj	Jh jkt flg ekj] ifyl vf/kdkjh gfj;k.kk
71-	ekFkj	Jh jkt flg ekFkj] Mh-vkb-th- ch-,l-,Q
72-	egfj;k] egkfj;k	Jh lHkk"k egkfj;k jktuhfrK jktLFkku
73-	j.kok	Jh eul[k j.kok] dfo vkj y[kd ¼jktLFkku½
74-	jk.kk] jkuk	Jh lr çdk'k jk.kk] Hkrio fo/kk;d fnYyh
75-	jkBh	fcxfM;j gkf'k;kj flg 1962 d Hkkjr phu ;) d uk;d

76-	jkor	Jh dkUgk jkor] ØkfUrdkjh LorU=rk lsukuh Qjhnkckn
77-	jk/kkok	Jh nkjkfl g igyoku] Hkkjrh; v/;{k Hkkjrh; tkV egklHkk fnYyh
78-	jko] ljko	Jh yky fl g jko ftykU;k;/kh'k t;iqj ¼jktLFkku½
79-	ykdMk	pkS lkgc fl g oek] Hkkjrh; e[;e=h fnYyh
80-	ykEck	lsB NTtw jke m|kxifr
81-	ykBj	Jh ekgu yky ykBj] iqfyl vf/kdkjh jktLFkku
82-	ykpc] ykgpc	Jh fot; fl g ykpc Hkkjrh; fo/kk;d ngyh
83-	ykgku	Mk- vkfnR;k ykgku] çkQslj bfrgkl vEckyk dsV
84-	ykj] ykjk	ohjUnz fl g ykj] lekftd dk;Zdrk tkV urk cyUn'kgj
85-	fotkjfu;k] fotjfu;k	Jh Hktu yky fotkjfu;k LoU=rk lsukuh vtesj
86-	flldjokj] flldjoky	Jhefr eerk lhdjokj] vkbZ-ih-,l- gfj;k.kk
87-	lkxfj;k] lkxjoky	Bkdqj n'kjkt tkV bfrgkldkj jktLFkku
88-	lhxM	pkS rkjkpUn lhxM] v/;{k jktLFkku tkV lekt lLFkku t;iqj
89-	lkxoku	pkS gokfl g lkxoku] v/;{k tkV vkj{k.k la?k"kZ lfefr iwoZ dekMsV
90-	lqMk	pkS deHkk jke vk;Z iwoZ jktuhfrd o lektlsoh jktLFkku
91-	lU/k] flU/kq	Jh Hkxr fl g] vej 'kghn ohj ØkfUrdkjh
92-	fl)w	Jh uotkr fl g fl)w] fØdsVj] lkaln o Vh-oh- dykdkj]
93-	flulluokj	egkjktk lwjtey Hkkjrh; fj;klr ds 'kkld
94-	lonk	Jh tljkt lonk lokfuo`r vkj-,-,l- lhdj ¼jkt-½
95-	flgkx] lgkx	Loñ pkS nohyky iwoZ ç/kkue=h Hkkjr] flj lk
96-	lgjkor	egkcyh lriky igyoku xkYM eSMy fotsrk dkeu oYFk xSEl
97-	ljkgk] fljkgk	pkS lkeiky 'kkL=h] iwoZ lkaln ,oa dsUnh; e=h Hkkjr
98-	fljkgh	Jh jk/kon fl g fljkgh] Hkkjrh; ç'kklfud lok vf/kdkjh e/;çns'k
99-	lgkju] lkj.k	nkÅyr jke lgkj.k] jktuhfrK o jktLFkku fdlku ;wfu;u ds lLFkkid
100-	'kkdhu] ';kdn	pkS ohjUnz fl g] iwoZ foÙk e=h o jkT; lHkk lkaln gfj;k.kk
101-	lkjkr] lkgjkr	Jh xqykc fl g lkjkr] Hkkjrh; ç'kklfud lok vf/kdkjh gfj;k.kk
102-	';kjku] ';kjk.k	pkS cyjkt fl g ';kjku] lektlsoh o çfl) vf/koDrk thn
103-	vxz gxk	Jh ljnkj fl g vxz iwoZ e=h mÙkjçns'k eFkjk
104-	gqMMk gMk	pkS HkwiUnz fl g gqMk] eq[;e=h gfj;k.kk
105-	gkyk gqy	Jh jkeyky gkyk tkV bfrgkldkj ys[kd
106-	cuhoky@ouhoky	Jhefr deyk cuhoky jkT;iky xqtjkr
107-	efyd] eyd] xBoky	pkS egUnz fl g efyd] iwoZ Mh-th-ih- gfj;k.kk
108-	dVkfj;k	Pkkñ yky pUn dVkfj;k] lkaln o e=h Hkkjr t;iqj
109-	dlok	pkS jkefl g dlok] iwoZ lkaln pw: jktLFkku
110-	[kktk	Jh jkr fl g [kktk] tkV 'kkld Vksad fj;klr jktLFkku
111-	cfy;ku	Loñ pkS egUnz fl g fVdSr çfl) fdlku urk fllkSyh

Hkkjrh; tkV lekt esa vU; dbZ xks= ds Hkh egRoiw.kZ rFkk ykdfç; 0'fDr gq, gSA ijUrq ;gka ij dN çeq[k xks= rFkk mul lEcfU/kr ek= ,d çfl) 0;fDr dk fooj.k fn;k x;k gSA

अपवित्र कल्पना भी उतनी ही बुरी होती है जितना बुरा अपवित्र कर्म होता है। – विवेकानन्द

जाट हीं तो है धर्मनिरपेक्षता का सहीं स्वरूप

& vkeçdk'k

समाज में जाट के समकक्ष अन्य जातियां, राजपूत, अहीर, गूजर, रोड़, सैनी आदि ऊपरी तौर पर जाट से समन्वय बनाये रखने का दिखावा करते हैं परन्तु ब्राह्मण द्वारा जाट के विरूद्ध भड़कीले एवं जहरीले प्रचार से प्रभावित होकर, सामाजिक तथा राजनीति कार्यकलापों में सदा दूर–दूर ही रहती है। जाट उनके निकट जाने का प्रयत्न भी करता है, समय–समय पर उन्हें अपना समर्थन भी देता है परन्तु जब जाट को उनके सहयोग एवं समर्थन की जरूरत पड़ती है तो वे जाट की सहायक सिद्ध नहीं होती। जहां तक हरिजन और पिछड़ी ताजियों का समबंध है वे गांव के समाज में विशेष तौर पर जाट सहारे पर जिन्दा है परन्तु जब जाट को उनके समर्थन की आवश्यकता पड़ती है तो वे जाट की बजाय ब्राह्मण के पाले में खड़ी मिलती है। ग्राम पंचायत के चुनाव से लेकर संसद के चुनावों तक वे ब्राह्मण से पूछकर वोट देती है और जाट को ठेंगा दिखाने में न शर्म करती और प अपने कृतघ्नता को ही ध्यान में लाती। लेकिन जाट फिर भी उनके कुकृत्य को दर गुजर कर देता है। हालांकि ब्राह्मण छुआ–छूत के विषय में सदा उनसे घृणा करता है, उनसे दूरी बनाये रखता है, अपने मंदिरों में भी उनके प्रवेश को बन्द रखता है, परन्तु फिर भी वे सदा ब्राह्मण के प्रचार के रंग में रगें रहते है। सन् 1966–67 में पं. भगवत दयाल शर्मा ने जाट–गैर जाट का नारा लगाया तो सब जातियां, शर्मा जी के साथ लामबन्द हो गई। वे मुख्यामंत्री बन गए और लग गए जाट के विरूद्ध जहर उगलने, 'मैंने इनकी पचास साला चौधर को उखाड़कर फैंक दिया है, अब इनकी पगड़ी और इनके डोंगें नुमाईश (नुमाईश) में रखवा दूंगा।' चौ. देवी लाल और प्रो. शेर सिंह की ओर इशारा कर कहते थे कि जब इनकी कुर्सी छिन गई थी तो इन्हें हरियाणा याद आया था और जब हरियाणा बन गया तो इन्हें फिर कुर्सी याद आई। अब मैंने इन्हें रातनीति में बहुत पिछे छोड़ दिया है। इसी प्रकार चौ. भजन लाल ने सन् 1991 में जाट गैर जाट का नारा लगाकर मुख्यामंत्री की कुर्सी हथिया ली। कुछ महीनों पहले मुख्यामंत्री हुकम सिंह द्वारा जाटों को दिया गया आरक्षण छीन लिया और भोला जाट देखता रह गया। फिर 2005 में गैर जाट का नारा देकर विधायकों का बहुमत अपने साथ जोड़ लिया था। लेकिन शुक्र है उस विदेशी महिला का जो जाट–गैर जाट के नारे से प्रभावित नहीं हुई और उसने हरियाणा के मुख्यामंत्री पद को नारे और भावनाओं की भेंट नहीं चढ़ने दिया और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को मुख्यामंत्री बनाया। हरियाणा में जाटों की संख्या 30–32 प्रतिशत और निःसदेंह दूसरी जातिया 70 प्रतिशत के लगभग है जबकि ब्राह्मण कुल जनसंख्यां के 7 प्रतिशत है परन्तु जाट के विरूद्ध उनके प्रचार के रंग में हरियाणा की ये सब बहुसंख्यक बिरादरियां, जितनी जल्दी रंगी जाती है यह भी किसी करिशमें से कम नहीं। जाट के विरूद्ध इस प्रकार के गंठजोड़ से यह सिद्ध होता है। कि इन लोगों का सच्चाई, न्याय, ईमानदारी, लोकतांत्रिक मान्याताओं एवं धर्मनिरपेक्षता से कुछ लेना देना नहीं। यह तो केवल एक बिरादरी के विरूद्ध ईष्या और द्वेष का ही कारण है। दूसरा कारण यह भी है कि जाट की शक्ति को कोई अकेली जाति चुनौति देने की स्थिति में नहीं है इसलिए वे सब मिलकर उसे परास्त करने का कुप्रास करती है। कारण जो भी हो ये उन सबका अनैतिक दुष्कर्म है क्योंकि जाट तो न किसी का बुरा करता है और न बुरा सोचता है। मगर फिर भी उसके विरूद्ध इस प्रकार का षड़यंत्र अव्यवहारिक और राजनीतिक बेईमानी है, समाज में जाट को स्वाभिमनी से न जीने देने की एक घटिया प्रवृत्ति है। उनके इस प्रकार के कुकृत्य से यह सिद्ध होता है कि वे ब्राह्मण को अपना समर्थन देकर समाज में अंधविश्वास को बढावा देते हैं या उसमें आस्था रखते हैं। धर्मनिरपेक्षता से कुछ लेना देना नहीं। जबकि जाट समाज में ईमानदाराना व्यवस्थाएं एवं परम्पराएं स्थापित कर सत्यता की मर्यादा कायम करता है। सब के प्रति सद्व्यवहार का पालन करता है और दुसरों के दुर्व्यवहार के सामने न कभी घुटने टेकता है और न समाज में अपने अकेलेपन से घबराता है। परिस्थितियां चाहे जो भी हों समाज में जाट की सच्ची और ईमानदाराना भूमिका को न कोई रोक सकता है और न कोई चुनौती दे सकता है कवि ने जाट के लिये ठीक ही कहा है कि **"चर्ख (आसमान) का क्यों गिला करें, दहर (जमाने) से खफा रहें, सारा जहां अदू (दुश्मन) सही आओ मुकाबला करें।"** हजारों साल से जाट इस जड़बुद्धि समाज से लोहा लेता चला आ रहा है यही जाट की जिन्दगी है और यही उसका जीवन है।

हजारों साल से लोग जाट कि हस्ती मिटाने के लिये अनर्गल प्रचार करते चले आ रहे है। परन्तु इन की मिथ्या आलोचनाएं, जाट के फलने–फूलने के लिये खाद का काम कर देती हैं। इन्होनें अनेक नारे और मुहावरे जाट के विरूद्ध घड़ रखें हैं। परन्तु वे जाट का कुछ न बिगाड़ सके। ब्राह्मण कहता है कि **जाट मरा जब जानियो जब तेरहमी हो जाये।** वह बेशक जाट को अपनी उक्ति से कोसता है परन्तु उसका भावार्थ यही है कि उसे जाट की मौत पर सन्देह है। बनिये का छोटा बच्चा अपने बापू से पूछता है कि बापू! जाट खड़ा अच्छा या पड़ा अच्छा? बनिया उत्तर देता है कि बेटा! जाट तो न खड़ा अच्छा ना पड़ा अच्छा, जाट तो मरा अच्छा। वह अपनी दुर्भावना से जाट के मरने की कामना करता है, उस जाट की जो उसके घर में घुसे चोरों को भगाता है, उसके घर में निकले सांप को मारता है परन्तु उस पर भी बनिया अपनी भावना दर्शाता है कि इसे सांप भी नहीं काटता। देखिये जो ब्राह्मण जाट का माल खाता है, उसकी दान–दक्षिणा पर अपने जीवन के दिन ओछे करता है वह उसके मरने की कामना करता है। जिस बनिये के घर से जाट चोरों को भगाता है, सांप को मारकर उसके जीवन की रक्षा करता है वही बनिया जाट के मरने की कामना करता है। जाट की जिन्दगी का अधार यही तो है कि जाट का बुरा चाहते है वह उनका भी भला करता है। ऐसे भले पुरूष को किसी की भी बददुआएं नहीं मिटा सकती। जो लोग जाट को आदमी भी नहीं मानते जाट उन्हीं के काम आता है। डूम ने जाट के लिये कहा है कि यदि इस धरती पर जाट न होते हम जैसे आदमियों को खेती करनी पड़ती। अर्थात जो डूम सौ प्रतिशत जाट पर अश्रित है वह भी जाट को आदमी नहीं मानता। पाकिस्तान बनने के बाद

शुरू–शुरू में जब पंजाबी इधर आये तो घर में पानी न होने के कारण उनकी स्त्रियां जाट के खेत में लगे ट्यूबवैल पर कपड़े धोने तथा स्नान के लिये जाया करती थी। एक दिन जाट ट्यूबवैल चला कर पास के खेत में चला गया। पंजाबी स्त्रियों ने कपड़े धोए और उनमें से एक नहाने लग गई, उसी दौरान जाट उन्हें दूर से आता दिखाई दिया। उनमें से एक नहाने वाली को कहने लगी, ''बन्दा औन्दा प्या!'' नहाने वाली ने पूछा, ''कित्थे'' दूसरी बोली, ''ओ वेखो!'' नहाने वाली कहने लगी, ''ओह बन्दा कित्थे है, ओ तां जट्ट है।'' पंजाबी स्त्री ने जाट को बन्दा (इंसान) मानने से ही इंकार कर दिया जाट के विरूद्ध हिन्दू धर्म की घृणा की यह पराकाष्ठा है कि वह उसे एक आदमी के रूप में भी मानने को तैयार नहीं। सन् 1957 में हिन्दी सत्याग्रह चल रहा था। तत्कालिन मुख्यामंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों जाट कालेज के प्रांगण में सोनीपत आये। जाट कालेज के विद्यार्थियों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। उन्होंनें प्रार्थना की कि केवल दो मिनट बोल लेने दो। उनके हाथ में उर्दू का दैनिक 'प्रताप' था। उसके सम्पादकीय में लिखा था, ''मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज पंजाब का हिन्दू और हरियाणा का जाट एक हो गए।'' कैरों साहब बोले कि इस पत्र का सम्पादक महाशय कृष्ण जो आन्दोलन का संचालक है और जिसके आह्वान पर तुम बावले हो रहे हो। वह तुम्हें हिन्दू मानने के लिये भी तैयार नहीं। हालांकि जाट हिन्दू नहीं लेकिन उसकी संकीर्णता देखिये वह जाट का इतना बड़ा समर्थन लेकर भी अपने बराबर माने की शालीनता तक भी नहीं दिखा रहा। इस देश का इतिहास गवाह है, रहबरे आज़म सर छोटूराम ने पंजाब का प्रिमियर निर्वाचित होने के बाद अपने गले का हार निकाल कर एक मुसलमान के गले में डालकर उसे प्रधानमंत्री बनाया, चौ॰ चरण सिंह ने प्रधामंत्री का पद ब्राह्मण मोरार जी देसाई को सौंप दिया, चौ॰ देवीलाल ने प्रधानमंत्री का ताज अपने सिंर से उतार कर राजपूत वी.पी सिंह के सिर पर रख दिया। दूसरी जाति के लोगों के लिये इतने बड़े त्याग को कोई उदाहरण नहीं मिलता। जाटों के त्याग के नाम पर देश का इतिहास गवाही देता है और गैर जाटों के त्याग के नाम पर देश का इतिहास खामोश है! फिर भी कोई जाट विरोध करे तो उसकी वाणी में कीड़े पड़ जाने चाहिये। जुल्म का यहीं पर अंत नहीं हो जाता, चरण सिंह और देवीलाल की कुर्बानियों का सिला, देसाई और वी.पी. सिंह ने यह दिया कि उन्होंनें एक साल के अन्दर–अन्दर ही चरण सिंह और देवीलाल को अपने मंत्री मंडल से बर्खास्त करवा दिया। त्यागियों के त्याग और कृतघ्नता की वह पराकाष्ठा थी। इन हिन्दुस्तानी हिन्दुओं द्वारा जाटों पर जुल्म ढ़ाने, उनके साथ अन्याय और अत्याचार करने, उनके साथ कदम–कदम पर द्रोह करने, उनका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण करने की लम्बी–लम्बी दास्तानें हैं। हिन्दुस्तानी राजनीति के शिखर पर तीन जाट चढ़े और तीनों ने जाट के त्याग और कुरबानी का इतिहास रचा जब कि दूसरी और इन हिन्दुस्तानी हिन्दुओं ने अवसर मिलते ही उनका गला काट लिया। इतने बड़े दुर्व्यवहारी लोगों के बीच हजारों साल से जाट कैसे रह रहा है यह भी एक विडम्बना है।

आर्यों (जाटों) के तीन वंश हैं, सूर्य वंश, चन्द्रवंश और यादव वंश। इन तीनों वशों के अढ़ाई–तीन हजार गोत्र है। इन के गोत्र बन्धु सारी दुनिया में पाये जाते है। चूंकि बोली चार कोस पर बदल जाती है, अतः हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के अलावा जाट के भाईचारे के लोग अपनी बिरादरी को, अपने देश काल के हिसाब से, अलग–अलग नामों से पुकारते हैं परन्तु वे सब आर्य हैं। उन सबका रंग रूप, चाल–ढाल, प्रवृत्ति–मनोवृत्ति, व्यवहार, शारीरिक बनावट, स्वभाव लगभग एक जैसा है। परन्तु उनकी यह पहचान कि वे हमारे भाई हैं केवल गोत्रों से पता चलता है, हमारे पड़ोसी देशों, चीन, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, मिश्र, श्री लंका, साऊदी अरब लगभग खाड़ी के सभी देशों में हम अपने गोत्र से उन्हें पहचान सकते हैं जैसे चीन के स्वर्गीय राष्ट्रपति माऊत्से तुंग, श्री लंका की पूर्व राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमार तुंग यानी तुंग गोत्र जाटों का है। इेरान के स्वर्गीय बादशाह रजा पहलवी, मिश्र के स्वर्गीय राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन नासर, फिलस्तीन के स्वर्गीय राष्ट्रपति यासर अराफात नासर, मुगलिया खानदान के जन्मदाता जहीरूद्दीन बाबर सूर्यवंशी और यहां तक कि इस्लाम के जन्मदाता पैगम्बर हजरत मुहम्मद कुरान तथा जर्मनी के तानाशाह हर हिटलर आर्य। नासर, पहलवी, सूर्यवंशी, कुरान, आर्य ये सब गोत्र आर्यों क्षत्रियों के हैं। कहते हैं कि गोती भाई बाकी सब आशनाई। आर्यों के जहां–जहां गोत्र मिलते हैं हम उन्हें चाहे जाट कहें, आर्य कहें या वंशीय पहचान से सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी कुछ भी कह सकते हैं। हमारे पूर्वज यानी आर्य लोग कबीलों की शक्ल में सारी दुनिया में घूमे और जहां–जहां गए उनमें से कुछ–कुछ लोग स्थान–स्थान पर बसते रहे। उन्होंनें वहां बसने वाली अपनी बिरादरी का नाम चाहे जो भी रख लिया हो परन्तु उन्होंनें आर्य, वंशीय और गोत्रीय पहचान को नहीं भूलाया। इस देश में बैठे हुये भी धुर अमेरिका, इंगलैड और रूस में बसं उन लोगों को, उनका वंश और गौत्र जानकर, उन्हें पहचाने और ढूंढ सकते हैं। आप उन्हें आर्य कहें, जाट कहें या उन्होंने अपने देश काल के हिसाब से अपनी बिरादरी का नाम जो भी अपना रखा है, वह कहें परन्तु वे यब हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, हमारा खून है, हमारी नस्ल है, हमारा कुनबा है, हमारा भाई–चारा है, उनके साथ कुछ मिलता होता तो 36 बिरादरी में कोई एक तो हमारा साथ देती, कोइ एक तो हमारे साथ रहती। इन सभी ने जाट को अलग निकाल रखा है, अलग मान रखा है, सबने जाट के विरूद्ध उपेक्षा का व्यवहार स्थापित किया हुआ है। जब भी काई अवसर आता है 35 बिरादरी एक और तथा जाट एक ओर। जाट, गैर–जाट, जाट–गैर जाट! जाट के साथ काई नहीं, कोई एक बिरादरी भी तो नहीं, किसी अन्य बिरादरी या जाति का कोई एक व्यक्ति भी तो नही। कैसे काम चलेगा? कैसे इनके साथ रहा जायेगा? भविष्य कैसे गुजरेगा? ये सब अन्य बिरादरियों तो प्रत्येक अवसर पर चूतड़ जोड़कर एक हो जाती हैं और जाट को दूध की मक्खी की भांति अलग निकाल कर फेंक दिया जाता है। पहले तलवार के बल पर राज लिये जाते थे अब राज लेने का तरीका बदल गया। अब तो सब से पूछकर, उनकी राय जानकर राजा बनाया जाता है। जाट तो इस देश में अल्पसंख्यक हैं। ऐसी परिस्थिति में ये हिन्दू लोग जाट को सत्ता के निकट नहीं जाने देंगें। इस सारे देश में तो क्या किसी प्रदेश में भी जाटों का बहुमत नहीं है। हर प्रदेश में जाट अल्पमत में हैं और इन लोगों का जाट से खास नफरत है। जाट का नाम तो इनके सामने ऐसा ले दिया जैसे कुत्ते को ईंट दिखा दी। इस विषय पर जाटों को गहन विचार करना होगा।

केवल कर्महीन ऐसे है जो भाग्य को कोसते है और जिनके पास शिकायतों का बाहुल्य है। – जवाहरलाल नेहरू

खेलों के साथ-साथ शिक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान

चौ. भरत सिंह मलिक स्पोर्ट स्कूल (Boys) व भाई सुरेन्द्र सिंह मलिक स्पोर्ट स्कूल (Girls)

Admission Open — **खेल गांव निडानी (जीन्द)** — **English Mediumn**

आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आपके क्षेत्र के खेल स्कूल जो पिछले २६ वर्षों से खेलो के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। स्कूल के छात्र व छात्राएं खेलों में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर अपनी व स्कूल की ख्याती प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। जिसमें यहां के खिलाड़ियों द्वारा 19 स्वर्ण पदकों के साथ 50 से ज्यादा अन्य पदक जीतकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। इन परिणामों के फलस्वरूप यहां के सैंकड़ों छात्र-छात्राए खेलों के आधार पर इस समय भिन्न-भिन्न विभागों में सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। हाल ही पिछले दिनों स्कूल की खिलाड़ियों की उपलब्धियों को देखते हुए केन्द्र व राज्य सरकार की खेल पॉलिसी के अतंर्गत चार करोड़ 98 लाख रूपये खेल के खिलाड़ियों को दिये जायेगें। जिसमें तीन करोड़ रूपये यहां की अर्न्तराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी कविता सिवाच को दिए जाएंगे। एक करोड़ 8 लाख रूपये अन्य खिलाड़ियों को दिए जायेगें। अतः आप सभी अभिभावकगण अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूलों की सेवाओं का लाभ उठाएं।

नोटः भारतीय खेल प्राधीकरण द्वारा 25 पहलवानों की डे बोंडींग स्कीम चलाई गई है, इस स्कीम में 8 से 14 वर्ष के बच्चे या राज्य स्तर पर कुस्ती में पदक विजेताओं को प्राथमिकता दी जाती है इस योजना में चयनित खिलाड़ियों को 2000 रू. की स्पोर्ट कीट व 1000 रू. मासिक वजिफा दिया जाता है।

स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए मुख्यअतिथि श्री मनोज सिंगल व पूर्व डी.जी.पी. डॅा0 महेन्द्र सिंह मलिक

विशेषताऐं :

- विशाल कम्पयूटर कक्ष।
- आधुनिक श्रव्य-संसाधानों द्वारा शिक्षा 2000 से अधिक पुस्तकों के संचय वाला पुस्तकालय।
- नियमित अध्यापक प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन।
- खेल-कूद का बड़ा मैदान।
- नियमित रूप से विद्वद्जनों द्वारा निरीक्षण।
- सामूहिक वाद-विवाद के अवसर

दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों का शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास के लिए खेलों को उचित महत्व दिया जाता है तथा आयु वर्ग के अनुसार खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सम्पादक मंडल

संरक्षक : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)
सम्पादक : श्री गुरनाम सिंह, आई.एफ.एस. (सेवानिवृत)
सह–सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान
साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक
प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो० : 9416282798
वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़

जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, चण्डीगढ़
फोन : 0172–2654932 फैक्स : 0172–2641127
Email : jat_sabha@yahoo.com

Postal Registration No. CHD/0107/2015-2017 **RNI No. CHABIL/2000/3469**

मुद्रक प्रकाशन एवं सम्पादक गुरनाम सिंह ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्टर्ज़, चंडीगढ़, फोन : 0172–2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2-बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27-ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया ।